कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/-रू.

माघ-फाल्गुन 2082, फरवरी 2026

VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

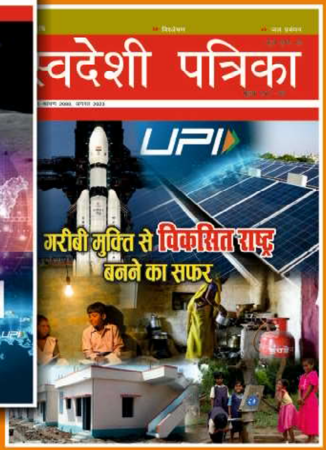

स्वदेशी
पत्रिका

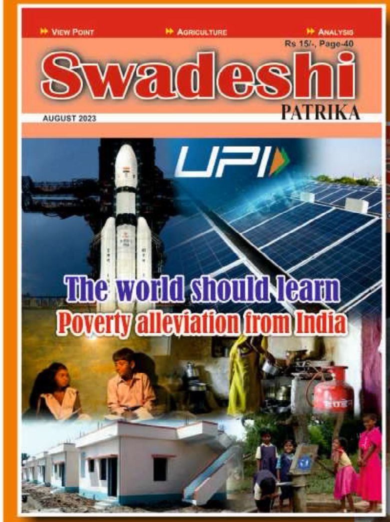

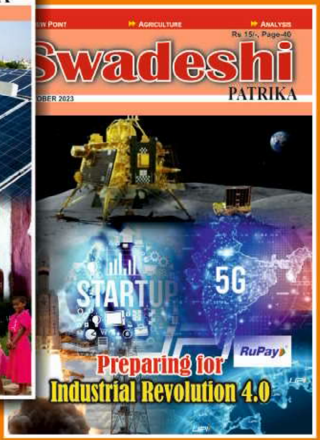

SWADESHI
Patrika

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–34, अंक–2
माघ–फाल्गुन 2082 फरवरी 2026

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–06

विकास और रोज़गारोन्मुख बजट
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 बजट
स्थिर विकास के साथ भविष्य की तैयारी
.... *डॉ. धनपत राम अग्रवाल*

10 बजट
विकास, विश्वास और बदलाव का नया खाका
.... *दुलीचंद कालीरमन*

12 बजट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद 15 प्रतिशत बढ़ा रक्षा बजट
.... *शिवनंदन लाल*

14 बजट
पर्यटन को मिलेगी मजबूती
.... *डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र*

16 बजट
बजट से मजबूत होगी आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद
.... *डॉ. जयप्रकाश मिश्र*

19 बजट
रेल सफर सुहावना करने का वादा!
.... *प्रहलाद सबनानी*

21 बजट
राज्यों की आर्थिकी और केंद्र की भूमिका
.... *अनिल तिवारी*

24 महाशिवरात्रि पर विशेष
भारतीय अनुभूति के निराले देवता हैं शिव
.... *वैदेही*

26 अंतर्राष्ट्रीय
बांग्लादेश में रहमान युग
.... *विनोद जौहरी*

28 आजकल
डिजिटल लत के साये में बचपन, टूटती जिंदगियां और अधूरी सोशल मीडिया सुरक्षा नीति
.... *अजय कुमार*

30 कारोबार
मुक्त व्यापार समझौते में भारत वसुधैव कुटुम्बकम के भाव
.... *स्वदेशी संवाद*

33 रिपोर्ट
योगी सरकार ने सिंगापुर में किये 6650 करोड़ के समझौते
.... *स्वदेशी संवाद*

पाठकनामा

बजट में स्वदेशी उत्पादन पर जोर

संघ बजट 2026–27 भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक रणनीतिक खाका है, जो अल्पकालिक लोकलुभावनवाद के बजाय दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देता है। पूंजीगत व्यय रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रूपये तक पहुंच गया (9 प्रतिशत की वृद्धि), जो अवसंरचना, विनिर्माण और रोजगार सृजन को ईंधन प्रदान करता है, साथ ही जीडीपी का 4.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखता है। यह दृष्टिकोण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से अर्थव्यवस्था की रक्षा करता है, जिसमें सात रणनीतिक क्षेत्रों – सेमीकंडक्टर, दुर्लभ मिट्टी खनिज, बायोफार्मा और कपड़ा – पर जोर देकर चीन पर आयात निर्भरता कम की जाती है।

यह बजट महत्वपूर्ण कमजोरियों का समाधान कर राष्ट्र को मजबूत बनाता है। दुर्लभ जीवाश्म गलियारों और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से ऊर्जा व तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जबकि बायोफार्मा कैंसर जैसी गैर–संचारी रोगों के लिए सस्ते बायोसिमिलर उपचार बढ़ावा देता है। क्रेडिट गारंटी और कौशल विकास से एमएसएमई को समर्थन मिलता है, जो रोजगार अंतर को पाटता है और चैंपियन उद्यमों को बढ़ावा देता है। रक्षा आधुनिकीकरण को 2.19 लाख करोड़ रूपये का पूंजीगत आवंटन – 22 प्रतिशत वृद्धि – मिलता है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन, मिसाइल और एंटी–ड्रोन सिस्टम के स्वदेशी उत्पादन, निर्यात क्षमता और पड़ोसी खतरों से निपटने में सक्षम बनाता है।

रेलवे को हाई–स्पीड गलियारों के लिए 2.78 लाख करोड़ रूपये आवंटित होकर लॉजिस्टिक्स लागत 14–16 प्रतिशत से प्रतिस्पर्धी स्तर तक कम करता है, निर्यात बढ़त और कनेक्टिविटी मजबूत करता है। कर संशोधन, जैसे एफएंडओ शुल्क वृद्धि, खुदरा सट्टेबाजी को रोकते हैं–95 प्रतिशत नुकसान उठाते हैं – सामान्य नागरिकों की रक्षा करते हुए इक्विटी लेनदेन कर नहीं बढ़ाते। एनिमेशन और गेमिंग (रीयल–मनी गेम्स) में ऑरेंज इकोनॉमी निवेश युवा रचनात्मकता को संभालता है, स्वास्थ्य व शिक्षा निदान के लिए एआई लोकतंत्रीकरण के वैश्विक रुझानों से तालमेल बिठाता है।

कुल मिलाकर, यह दूरदर्शी योजना विकसित भारत 2047 से संरेखित है, राजकोषीय संयम के साथ जमीनी सशक्तिकरण को संतुलित करती है – चुनावी वर्ष के उपहार नहीं, अपितु स्थायी समृद्धि।

विजित कुमार, क्षेत्र मीड़िया प्रमुख, पूर्वोत्तर भारत, स्वदेशी जागरण मंच

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

इस वर्ष का केंद्रीय बजट एक विकसित भारत की परिकल्पना को दर्शाता है। इसे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ तैयार किया गया है, और यह अगले 25 वर्षों में होने वाले परिवर्तन की एक मजबूत नींव रखेगा।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

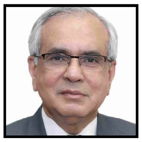

वित्तमंत्री ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 12 लाख करोड़ रु. के पूंजीगत व्यय के साथ एक दीर्घकालिक आधार तैयार किया है।

राजीव कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग

भारत समावेशी महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करते हुए विकसित भारत की दिशा में आत्मविश्वासपूर्ण कदम बढ़ाना जारी रखेगा... हमने सार्वजनिक निवेशों पर जोर देते हुए राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखी है।

निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, भारत

बजट 2026–27 मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार वृद्धि को प्रोत्साहित करता दिखाई देता है। साथ ही, यह गांवों और किसानों को सशक्त बनाते हुए महंगाई को नियंत्रित रखने का प्रयास करता है।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

ट्रंप के टैरिफ झटके पर न्यायिक रोक: अमेरिका-भारत आर्थिक संबंधों के लिए क्या है मायने?

संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने 6–3 के बहुमत वाले ऐतिहासिक फैसले में डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा आपातकालीन प्रावधानों के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को निरस्त कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि मौजूदा कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम पर असीमित और व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। इस फैसले ने ट्रंप प्रशासन की आक्रामक टैरिफ नीति पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सीमा लगा दी है और वैश्विक व्यापार वार्ताओं में एक नई अनिश्चितता भी पैदा कर दी है। भारत के लिए यह फैसला एक नाजुक समय पर आया है। हाल के महीनों में बढ़ते टैरिफ खतरों के बीच नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच एक अंतरिम व्यापार व्यवस्था के लिए प्रारंभिक ढांचे पर सहमति बनने की खबरें सामने आई थीं। लेकिन अमेरिकी प्रशासन की ओर से बार–बार बदलते संकेतों और परस्पर विरोधी बयानों ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी। भारत में भी इस बात को लेकर आलोचना हुई कि ऐसी अनिश्चित परिस्थितियों में व्यापार समझौते की जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत ने कथित तौर पर आगे की वार्ताओं को फिलहाल टाल दिया है, ताकि नई परिस्थितियों का आकलन किया जा सके। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही आक्रामक टैरिफ वृद्धि अमेरिकी व्यापार नीति की पहचान बन गई थी। समर्थकों का तर्क था कि यह नीति दशकों से जारी औद्योगिक गिरावट को रोकने और घरेलू उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है। आलोचकों का मानना था कि व्यापक संरक्षणवाद अंततः आर्थिक रूप से आत्मघाती साबित हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के राजनीतिक समर्थकों के कुछ वर्गों में भी इस नीति की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर सवाल उठने लगे थे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय तक एक उच्च लागत लेकिन अत्यंत प्रतिस्पर्धी औद्योगिक अर्थव्यवस्था रहा है। बीसवीं सदी के अधिकांश समय में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, वस्त्र और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उत्पादन में उसकी अग्रणी भूमिका रही। उस दौर में टैरिफ घरेलू उद्योग को सुरक्षा देने के साथ–साथ संघीय सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी थे। समय के साथ, विशेषकर वैश्वीकरण के दौर में, अमेरिकी नीति निर्माताओं ने आयात शुल्क को धीरे–धीरे कम करना शुरू किया ताकि उपभोक्ताओं को सस्ते आयात उपलब्ध हो सकें। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद व्यापार बाधाओं में कमी को संस्थागत रूप मिला और यह प्रवृत्ति और गहरी हो गई। इसका परिणाम एक संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में सामने आया। सस्ते आयातों से अमेरिकी उपभोक्ताओं को लाभ तो मिला, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार घटने लगा। हालांकि कहानी यहाँ पूरी नहीं होती। जैसे–जैसे निम्न–स्तरीय औद्योगिक उत्पादन एशिया और अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित हुआ, अमेरिका ने उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों, फार्मास्यूटिकल्स, उन्नत रक्षा प्रणालियों, बौद्धिक संपदा, वित्तीय सेवाओं और अंतरिक्ष तकनीक जैसे क्षेत्रों में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली।

1999 में यूरो के आगमन के बाद भी वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में अमरीकी डॉलर की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत के आसपास बनी रही। यह इस बात का संकेत है कि अमेरिकी आर्थिक शक्ति केवल पारंपरिक विनिर्माण पर आधारित नहीं थी, बल्कि तकनीकी और वित्तीय प्रभुत्व पर भी टिकी हुई थी। दूसरे शब्दों में, अमेरिका का औद्योगिक ढांचा पूरी तरह ढहा नहीं, बल्कि उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था के उच्चतम स्तरों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि ऊँचे टैरिफ से एक ओर संघीय राजस्व में वृद्धि होगी और दूसरी ओर घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलेगा। 2025 में टैरिफ से प्राप्त राजस्व लगभग 287 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया, जबकि पहले यह 70 से 80 अरब डॉलर के बीच रहता था। फिर भी कुल संघीय राजस्व में इसकी हिस्सेदारी केवल 4 से 5 प्रतिशत के आसपास ही रही, जबकि ऐतिहासिक रूप से यह लगभग 2 प्रतिशत रही है। लेकिन संघीय आय का अधिकांश हिस्सा आज भी आयकर और पेरोल कर से ही आता है। टैरिफ का व्यापक आर्थिक प्रभाव हालांकि अधिक स्पष्ट रहा है। आयात शुल्क वस्तुतः आयातित वस्तुओं पर लगाया गया एक प्रकार का उपभोग कर होता है, इसका सीधा बोझ विदेशी निर्यातकों पर नहीं, बल्कि घरेलू आयातकों और अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है। आयात महंगे होने से क्रय शक्ति कम होती है, महंगाई का दबाव बढ़ता है और मौद्रिक नीति के लिए नई चुनौतियां पैदा होती हैं। ऐसे वातावरण में ब्याज दरों में संभावित वृद्धि आर्थिक गतिविधियों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। दशकों तक अमेरिकी बाजार तक खुली पहुंच ने दुनिया भर के देशों के साथ राजनीतिक और व्यावसायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। जो देश अमेरिका को निर्यात करते थे, वे अक्सर अमेरिकी कंपनियों को अपने बाजारों में निवेश और व्यापार के अवसर भी देते थे। इससे मुनाफा, रॉयल्टी और कर राजस्व के रूप में अमेरिका को भी लाभ मिलता था। उच्च टैरिफ इस व्यवस्था की दिशा को उलट देते हैं। आर्थिक परस्पर निर्भरता को मजबूत करने के बजाय वे देशों को अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक व्यापार साझेदार तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी संदर्भ में वैश्विक आर्थिक संरचना में धीरे–धीरे बदलाव के संकेत भी दिखाई देने लगे हैं। व्यापार भुगतान में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग में वृद्धि और ब्रिक्स जैसे समूहों की बढ़ती सक्रियता इस व्यापक पुनर्संतुलन की ओर इशारा करती है। हालांकि डॉलर का प्रभुत्व अभी भी कायम है, लेकिन लगातार व्यापार तनाव दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों को तेज कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति कांग्रेस से व्यापक टैरिफ अधिकार प्राप्त करने के लिए कानून पारित कराने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन बहुमत सीमित है और व्यापार नीति को लेकर आंतरिक मतभेद भी स्पष्ट हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कार्यपालिका की एकतरफा शक्ति पर संस्थागत नियंत्रण स्थापित करता है।

अमरीकी प्रशासन कुछ वैकल्पिक उपायों पर भी विचार कर रहा है, जिनमें सेक्शन 122 के तहत अस्थायी वैश्विक टैरिफ शामिल है। प्रारंभिक प्रस्ताव 10 प्रतिशत का था जिसे बाद में 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात सामने आई। यदि इसे मौजूदा लगभग 3.3 प्रतिशत के 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' शुल्क के साथ जोड़ा जाए तो कुल प्रभावी टैरिफ लगभग 18 प्रतिशत के आसपास बैठता है। यह पहले के प्रस्तावित 25 प्रतिशत से कम है, लेकिन यदि इसे सभी देशों पर समान रूप से लागू किया जाता है तो भारत जैसे देशों के लिए अपेक्षित विशेष लाभ कम हो सकते हैं। इस नई स्थिति में भारत को अपनी व्यापार रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। यदि भेदभावपूर्ण टैरिफ कानूनी रूप से सीमित हो जाते हैं तो भारत को वार्ता में कुछ अतिरिक्त गुंजाइश मिल सकती है। साथ ही अमेरिकी नीति की अनिश्चितता को देखते हुए सतर्कता भी आवश्यक है। वार्ताओं को फिलहाल स्थगित करना संभवतः पीछे हटना नहीं, बल्कि एक सामरिक विराम है। इस पूरे घटनाक्रम का व्यापक संदेश स्पष्ट है। टैरिफ अल्पकालिक राजनीतिक उपकरण तो हो सकते हैं, लेकिन वे प्रतिस्पर्धात्मकता, नवाचार और दीर्घकालिक औद्योगिक नीति का विकल्प नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह भी दर्शाता है कि आर्थिक राष्ट्रवाद के दौर में भी अमेरिकी शासन प्रणाली में संस्थागत संतुलन और नियंत्रण की भूमिका निर्णायक बनी रहती है।

अब यह देखना बाकी है कि ट्रंप प्रशासन इस फैसले के बाद अपनी रणनीति को संशोधित करता है या टकराव का रास्ता अपनाता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि न्यायपालिका ने कार्यपालिका की व्यापार शक्ति पर एक महत्वपूर्ण सीमा तय कर दी है। भारत के लिए सबसे विवेकपूर्ण रणनीति यही होगी कि वह सतर्कता, लचीलापन और अपने वार्ताकारी हितों की रक्षा के साथ आगे बढ़े।

विकास और रोज़गारोन्मुख बजट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी, 2026 को अपना लगातार नौवां बजट पेश किया। इसमें कोई संशय नहीं कि वैश्विक मुश्किलों और अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ वृद्धि की वजह से अनिश्चित वैश्विक बाज़ार, और बड़ी आर्थिक ताकतों द्वारा ज़रूरी मिनरल, सेमीकंडक्टर और कई दूसरी चीज़ों की सप्लाई सहित ग्लोबल वैल्यू चेन के हथियारीकरण की कोशिश, भुगतान प्रणाली के दुरुपयोग के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार चौथे साल भी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर अच्छी स्थिति में है। रुपये की गिरती कीमत, लगातार व्यापार और भुगतान घाटे और बढ़ते सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश बढ़ने की अनिश्चितता के कारण वित्त मंत्री के सामने बहुत सारी चिंताएँ भी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ने अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पेश की है, जिसमें उन चिंताओं की बातें भी उठाई गई हैं, खासकर रुपये की गिरती कीमत, एफडीआई में लगातार कमी, जिससे निवल एफडीआई ऋणात्मक हो रही है, और उसके लिए सही उपाय अपनाने की ज़रूरत है। सर्वेक्षण ने न केवल समाज के लिए, बल्कि युवाओं की डिजिटल लत से अर्थव्यवस्था को होने वाले खतरों और कई दूसरे मुद्दे भी उठाए हैं। ज़ाहिर है, इस बजट में उन सभी पर बात नहीं हो सकी, लेकिन ऐसा लगता है कि बजट में नीति की बड़ी दिशा साफ़ है और नीति यह है कि भारत न सिर्फ़ ग्लोबल उथल–पुथल से खुद को बचाने की कोशिश करेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाएगा, न सिर्फ़ अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाएगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अहम खिलाड़ी भी बनेगा।

बजट में सात रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का प्रस्ताव है। लंबे समय से, भारत सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मैटीरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और कैपिटल गुड्स की सप्लाई के लिए विदेशों, खासकर चीन पर निर्भर रहा है। इन सभी को बजट में जगह दी गई है और इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए रणनीति भी बनायी गई है। इससे न केवल

यह बजट मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार वृद्धि को प्रोत्साहित करता दिखाई देता है। साथ ही, यह गांवों और किसानों को सशक्त बनाते हुए महंगाई को नियंत्रित रखने का प्रयास करता है।

– **डॉ. अश्वनी महाजन**

चीन पर हमारी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए ग्लोबल वैल्यू चेन के हथियार बनने से भी अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकेगा। पहले से ही न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया रेयर अर्थ मटीरियल की सप्लाई को लेकर चीन के नखरे झेल रही है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास रेयर अर्थ मेटीरियल नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में माइनिंग, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कमी है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे मिनरल से भरपूर राज्यों को डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने, माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में मदद दी गई है।

बजट में पेश की गई कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट (सीआईई) को बढ़ाने की योजना, हाई–वैल्यू टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सीआईई की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करेगी। देश कंटेनरों की भारी कमी और चीन पर भयंकर निर्भरता का सामना कर रहा है, ऐसे में दुनिया भर में मुकाबला करने वाला कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की घोषणा, 710,000 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक योजना एक बड़ा क़दम है।

मैन्युफैक्चरिंग को एक और बड़ा बढ़ावा, बायो फार्मा में मिला है। यह ध्यान देने वाली बात है कि बायो फार्मा, जिसमें बायो सिमिलर्स भी शामिल हैं, कई नॉन–कम्युनिकेबल बीमारियों (एनसीडी) के इलाज में क्रांति ला सकते हैं।

श्रम प्रधान टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक व्यापक प्लान, बजट में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इसके अलावा, 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' पहल की शुरुआत से खादी और हैंडलूम को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, मध्यम, लघु एवं कुटीर उद्योगों को समर्थन करने के लिए 10000 करोड़ रुपये का आवंटन एक अहम कदम है।

बजट में पूंजीगत निवेश को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, और प्रभावी पूंजीगत निवेश जीडीपी का 4.4 प्रतिशत है, जो न सिर्फ अब तक का सबसे ज़्यादा है, बल्कि यह राजकोषीय घाटे से भी ज़्यादा है।

बजट में पूंजीगत निवेश को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, और प्रभावी पूंजीगत निवेश जीडीपी का 4.4 प्रतिशत है, जो न सिर्फ अब तक का सबसे ज़्यादा है, बल्कि यह राजकोषीय घाटे से भी ज़्यादा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सरकार उधार तो ले रही है, लेकिन उपभोग के लिए नहीं, बल्कि असल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए।

नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे सकते हैं।

प्रस्तावों का एक और अहम हिस्सा विकसित भारत के लिए प्रोफेशनल्स का सृजन है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अगले पाँच वर्षों में 1,00,000 एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स (एएचपी), 1.5 लाख केयरगिवर्स और 20,000 वेटेरिनरी प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये सभी पहलें कौशल की कमी को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से बजट में मत्स्य क्षेत्र की वृद्धि के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास, तटीय इलाकों में फिशरीज़ वैल्यू चेन को मजबूत करना, फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन्स के साथ स्टार्टअप्स और महिला समूहों को जोड़ना, क्रेडिट–लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम लागू करना तथा लाइवस्टॉक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन्स जैसे उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र को समर्थन देना शामिल है। साथ ही, लाइवस्टॉक एंटरप्राइजेज़ का आधुनिकीकरण और डेयरी व पोल्ट्री के लिए एकीकृत वैल्यू चेन विकसित करने की भी योजना है।

इसके अतिरिक्त, तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी फसलों के साथ–साथ उच्च–मूल्य कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। पहाड़ी इलाकों में बादाम, अखरोट और पाइन नट्स जैसे नट्स भी ग्रामीण आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बजट 2026–27 में इसके लिए आवश्यक प्रावधान और राशि आवंटित की गयी है।

आंकड़े निश्चित रूप से प्रभावशाली हैं। हम देखते हैं कि 7.4 प्रतिशत की विकास दर, 2 प्रतिशत से कम महंगाई और लगातार घटता राजकोषीय घाटा यह संकेत देते हैं कि अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है। हालांकि, रुपये की गिरती कीमत, वैश्विक उथल–पुथल, टैरिफ और वैल्यू चेन के हथियारीकरण जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। एक बार फिर, बजट में राजकोषीय घाटे को घटाकर 4.3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। उम्मीद की जा सकती है कि महंगाई नियंत्रण में रहेगी।

कुल मिलाकर, यह बजट मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार वृद्धि को प्रोत्साहित करता दिखाई देता है। साथ ही, यह गांवों और किसानों को सशक्त बनाते हुए महंगाई को नियंत्रित रखने का प्रयास करता है।❑❑

स्थिर विकास के साथ भविष्य की तैयारी

विश्व अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रही है, जिसमें आर्थिक स्थिरता और अनिश्चितता साथ–साथ चल रही हैं। भू–राजनीतिक तनाव, वैश्विक व्यापार संरचना में परिवर्तन, ऊर्जा कीमतों की अस्थिरता, मुद्रा उतार–चढ़ाव और तीव्र तकनीकी बदलाव ने विकास के पारंपरिक ढाँचों को चुनौती दी है। इस पृष्ठभूमि में भारत का बजट 2026–27 केवल आय–व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक दृष्टि का परिचायक है। यह बजट इस बात का संकेत देता है कि भारत वैश्विक अस्थिरता के बीच अपनी विकास यात्रा को स्थिर और संरचनात्मक आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 इस व्यापक तस्वीर को और स्पष्ट करता है। सर्वेक्षण बताता है कि वैश्विक विकास दर अपेक्षाकृत धीमी होने के बावजूद भारत अपनी आंतरिक मांग, निवेश और सेवा क्षेत्र की ताकत के कारण मजबूत हुआ है। लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि दर यह संकेत देती है कि भारत केवल चक्रीय उछाल का लाभ नहीं उठा रहा, बल्कि एक दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है। परंतु उच्च वृद्धि अपने साथ नई जिम्मेदारियाँ और चुनौतियाँ भी लेकर आती है – विशेष रूप से रोजगार, बाह्य क्षेत्र संतुलन, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और वैश्विक व्यापार संबंधों के संदर्भ में।

बजट 2026–27 का केंद्रीय विचार निवेश आधारित विकास है। सरकार ने पूंजीगत व्यय को उच्च स्तर पर बनाए रखकर स्पष्ट किया है कि दीर्घकालिक उत्पादक क्षमता का निर्माण प्राथमिकता है। परिवहन, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना में निवेश केवल वर्तमान आर्थिक गतिविधि को गति नहीं देता, बल्कि भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी मजबूत करता है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने का प्रयास यह दर्शाता है कि विकास और वित्तीय अनुशासन को परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक माना जा रहा है। यह संतुलन आर्थिक विश्वसनीयता को बढ़ाता है और निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है।

कृषि क्षेत्र की भूमिका इस आर्थिक ढांचे में केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक स्थिरता और ग्रामीण आय का आधार भी है। बजट में मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण पर दिया गया जोर यह संकेत देता है कि कृषि को पारंपरिक उत्पादन मॉडल से आगे ले जाकर आय उन्मुख गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है। जब किसान केवल कच्चा उत्पाद बेचने के बजाय प्रसंस्कृत और उच्च मूल्य वाले उत्पादों की ओर बढ़ते हैं, तो आय स्थिरता और ग्रामीण

बजट 2026–27 यह संकेत देता है कि भारत विकास को केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि संरचनात्मक स्थिरता के साथ देख रहा है।

– डॉ. धनपतराम अग्रवाल

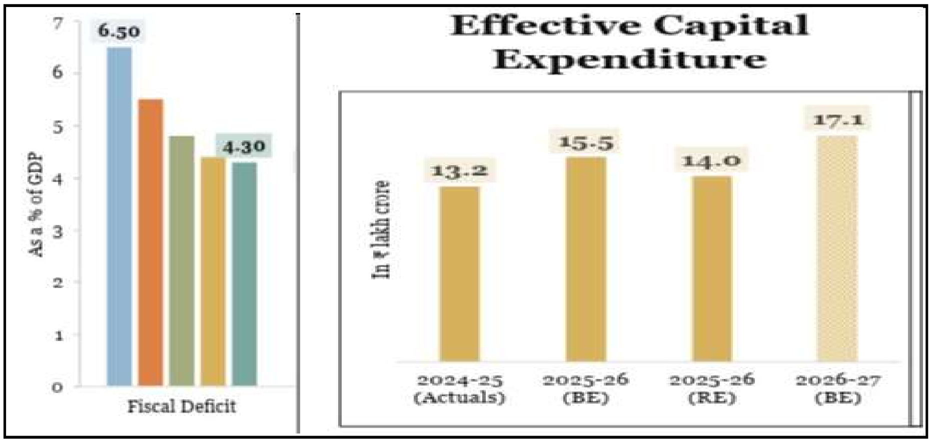

रोजगार दोनों में सुधार होता है। यह परिवर्तन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ–साथ राष्ट्रीय विकास में भी योगदान देता है।

विनिर्माण और एमएसएमई क्षेत्र आर्थिक संरचना का वह हिस्सा हैं जहाँ विकास का सीधा संबंध रोजगार से जुड़ता है। औद्योगिक ढांचे में निवेश, तकनीकी उन्नयन और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान दिला सकता है। एमएसएमई क्षेत्र का महत्व केवल उत्पादन में नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक गतिशीलता में भी है। छोटे उद्योग स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधि को बढ़ाते हैं और व्यापक रोजगार सृजन का माध्यम बनते हैं। इस दृष्टि से बजट का औद्योगिक फोकस दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है।

सेवा क्षेत्र भारत की विकास यात्रा का प्रमुख इंजन बना हुआ है। डिजिटल सेवाएं, वैश्विक क्षमता केंद्र और ज्ञान आधारित उद्योग भारत को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में आगे रखते हैं। सेवा निर्यात देश के बाह्य संतुलन को मजबूत करता है और विदेशी मुद्रा प्रवाह सुनिश्चित करता है। इसी क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उभरता प्रभाव नई संभावनाओं और चुनौतियों दोनों को सामने लाता है। पारंपरिक आईटी सेवाओं पर दबाव पड़ सकता है, परंतु उच्च कौशल आधारित सेवाओं की मांग बढ़ेगी। बजट में डिजिटल कौशल और तकनीकी अवसंरचना पर जोर इस संक्रमण को अवसर में बदलने का प्रयास है।

बाह्य क्षेत्र की स्थिति भारत की समग्र आर्थिक सेहत का महत्वपूर्ण संकेतक है। माल व्यापार में घाटा संरचनात्मक है, पर सेवा क्षेत्र का अधिशेष इस असंतुलन को काफी हद तक संतुलित करता है। चालू खाता घाटा नियंत्रित स्तर पर बना हुआ है और विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। रुपये पर दबाव वैश्विक परिस्थितियों का परिणाम है, पर निर्यात प्रतिस्पर्धा और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाकर इस दबाव को कम किया जा सकता है।

मुक्त व्यापार समझौतों की चर्चा इस संदर्भ में विशेष महत्व रखती है। अमेरिका और यूरोप के साथ संभावित व्यापारिक साझेदारी भारत के लिए बड़े बाजार और तकनीकी सहयोग के अवसर खोल सकती है। परंतु इन समझौतों का प्रभाव समान रूप से सकारात्मक नहीं होगा। कृषि और छोटे उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उदारीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध और संतुलित रखना आवश्यक है, ताकि घरेलू उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन, ऊर्जा संक्रमण और तकनीकी प्रतिस्पर्धा नई आर्थिक धुरी का निर्माण कर रहे हैं। भारत के लिए यह अवसर है कि वह विनिर्माण, डिजिटल सेवाओं और नवाचार के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत करे। युवा कार्यबल, अवसंरचना विस्तार और तकनीकी अनुकूलन क्षमता भारत की प्रमुख ताकत हैं, पर रोजगार सृजन, व्यापार संतुलन और कौशल उन्नयन जैसी चुनौतियाँ भी सामने हैं।

अंततः बजट 2026–27 यह संकेत देता है कि भारत विकास को केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि संरचनात्मक स्थिरता के साथ देख रहा है। कृषि, उद्योग और सेवा – तीनों क्षेत्रों का संतुलन, निवेश आधारित रणनीति और वैश्विक परिवर्तनों के प्रति सजग दृष्टिकोण भारत को दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती की दिशा में ले जा सकता है। यह यात्रा आसान नहीं है, पर स्पष्ट नीति दिशा और सतत् क्रियान्वयन भारत को अवसरों का लाभ उठाने और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बना सकते हैं।

मूल समस्याः अनुसंधान और उत्पादकता का अभाव

विनिर्माण का जीडीपी में हिस्सा

- भारतः ~16 प्रतिशत
- चीनः ~28 प्रतिशत
- दक्षिण कोरियाः ~26 प्रतिशत

R&D व्यय (% of GDP)

- भारतः ~0.7 प्रतिशत
- अमेरिकाः ~3 प्रतिशत +
- चीनः ~2.4 प्रतिशत
- दक्षिण कोरियाः ~4.5 प्रतिशत

इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में भारत की आर्थिक रणनीति का सार यही है – विकास को स्थिरता से जोड़ना, और स्थिरता को भविष्य की तैयारी से।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 और केंद्रीय बजट में भारत के बाह्य क्षेत्र की स्थिति पर गंभीर ध्यान दिया गया है। दो प्रमुख संकेतक चिंता के विषय हैंः 1. उच्च व्यापार घाटा, 2. रुपये का क्रमिक अवमूल्यन। इन दोनों को अल्पकालिक उतार–चढ़ाव के रूप में नहीं, बल्कि विनिर्माण क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरी के रूप में देखा गया है। स्पष्ट है कि भारत की प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरी का मूल कारण निम्न अनुसंधान निवेश है।

व्यापार घाटे की संरचना

अनुमानित परिदृश्य (2025–26)

- वस्तु निर्यातः ~+450 बिलियन
- वस्तु आयातः ~+700 बिलियन
- व्यापार घाटाः ~+250 बिलियन

व्यापार घाटा और रुपये का अवमूल्यन केवल आर्थिक संकेतक नहीं हैं – वे भारत की तकनीकी और औद्योगिक संरचना का दर्पण हैं। स्थायी समाधान केवल "मुद्रा प्रबंधन" या "शुल्क नीति" में नहीं, बल्कि अनुसंधान–आधारित स्वदेशी, उच्च–गुणवत्ता और निर्यातोन्मुख विनिर्माण मॉडल में निहित है। यही आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वास्तविक आर्थिक आधार होना चाहिये। ❑❑

विकास, विश्वास और बदलाव का नया खाका

भारत की अर्थव्यवस्था इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। वैश्विक मंदी की आशंकाएँ, भू–राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव और तकनीकी परिवर्तन – इन सबके बीच देश के सामने तेज़, समावेशी और टिकाऊ विकास की चुनौती है। ऐसे समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट केवल आय–व्यय का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला नीति–पत्र है। यह बजट स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार विकास की गति बनाए रखते हुए सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और निवेश– तीनों को संतुलित करना चाहती है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है। बजट में राजकोषीय घाटे को 4.3 प्रतिशत तक नियंत्रित रखते हुए विकास पर खर्च बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है। यह संतुलन आसान नहीं होता, क्योंकि एक ओर सरकार को निवेश बढ़ाना है, दूसरी ओर वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखना है।

सरकार ने पूंजीगत व्यय को उच्च स्तर पर बनाए रखा है। यह संकेत देता है कि विकास का इंजन अभी भी सार्वजनिक निवेश ही रहेगा, जो निजी निवेश को आकर्षित करने का आधार बनेगा। बजट का सबसे बड़ा फोकस बुनियादी ढाँचे पर है। अवसंरचना विकास हेतु 12.2 लाख करोड़ रुपये सड़कों, रेल, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में निवेश की घोषणा की गई है। अवसंरचना पर खर्च का आर्थिक "गुणक प्रभाव" सबसे अधिक होता है – यह रोजगार पैदा करता है, उद्योगों को गति देता है और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है।

रेलवे के लिए रिकॉर्ड आवंटन किया गया है, जिसमें 7 नए हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर, सेमी–हाई–स्पीड ट्रेनें, माल ढुलाई गलियारे और स्टेशन आधुनिकीकरण शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण और मल्टी–मॉडल परिवहन पर विशेष बल दिया गया है। इससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार की लागत भी घटेगी।

विकसित भारत का सपना केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि निरंतर नीति–सुधार, निवेश और जनभागीदारी से ही साकार होगा और यह बजट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

– दुलीचंद कालीरमन

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बजट में 1.6 लाख करोड़ रूपये के आबंटन द्वारा इसे प्राथमिकता दी गई है। किसानों की आय बढ़ाने, जोखिम कम करने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। सिंचाई परियोजनाओं, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और कृषि तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया है।

कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाया गया है, जिससे किसानों को सस्ती दरों पर पूंजी उपलब्ध होगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ती दरों पर अधिक पूंजी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। जिससे भंडारण, कोल्ड–चेन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश से कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ेगा और किसानों की आय में स्थिरता आएगी।

बजट में रक्षा के लिए लगभग 7.85 लाख करोड़ रूपये के आसपास प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाता है। भारत पहले से ही विश्व के शीर्ष रक्षा खर्च करने वाले देशों में शामिल है, और यह बजट उस प्रवृत्ति को जारी रखता है। यह राशि केवल युद्धक तैयारियों के लिए नहीं, बल्कि सैन्य आधुनिकीकरण, अनुसंधान, पेंशन और घरेलू उद्योग के विकास के लिए भी उपयोग की जाएगी।

स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च में वृद्धि इस बजट की महत्वपूर्ण विशेषता है। ग्रामीण स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत करने, नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और डिजिटल हेल्थ सेवाओं के विस्तार की योजना बनाई गई है। महामारी के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता और स्पष्ट हो गई है। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और शोध पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई पीढ़ी को भविष्य की अर्थव्यवस्था के अनुरूप तैयार करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह निवेश दीर्घकाल में भारत की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगा।

कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाया गया है, जिससे किसानों को सस्ती दरों पर पूंजी उपलब्ध होगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ती दरों पर अधिक पूंजी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है।

भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसे रोजगार में बदलना सबसे बड़ी चुनौती भी है। बजट में कौशल विकास कार्यक्रमों, स्टार्ट–अप समर्थन और श्रम–प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण सुविधा, डिजिटल समर्थन और बाज़ार तक पहुँच बढ़ाने की योजनाएँ शामिल हैं। यही क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार पैदा करता है, इसलिए इसकी मजबूती अर्थव्यवस्था की मजबूती से सीधे जुड़ी है।

भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन योजनाएँ जारी रखी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और हरित तकनीक जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ तकनीकों में निवेश बढ़ाया गया है। इससे न केवल पर्यावरणीय लक्ष्य पूरे होंगे, बल्कि ऊर्जा आयात पर निर्भरता भी घटेगी।

डिजिटल अवसंरचना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास के नए इंजन के रूप में देखा जा रहा है। डिजिटल भुगतान, ई–गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और डेटा अवसंरचना पर निवेश बढ़ाया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार घटेगा और सेवाओं की पहुँच तेज़ होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार डिजिटल विभाजन को कम करेगा और नई आर्थिक गतिविधियों के द्वार खोलेगा।

मध्यम वर्ग के लिए कर ढाँचे में सरलीकरण और जीएसटी के माध्यम से कुछ राहत के संकेत दिए गए हैं, जिससे उपभोग बढ़ने की उम्मीद है। उपभोग में वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह उत्पादन और निवेश दोनों को प्रोत्साहित करती है। साथ ही कर आधार बढ़ाने और अनुपालन सुधारने के लिए तकनीक का उपयोग जारी रहेगा।

हालाँकि केन्द्रीय बजट विकासोन्मुख है, लेकिन चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना, रोजगार सृजन की गति बढ़ाना, ग्रामीण आय में सुधार और निजी निवेश को प्रोत्साहित करनाकृये सभी कठिन कार्य हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का प्रभाव भी भारत पर पड़ सकता है।

कुल मिलाकर, बजट 2026–27 संतुलित, दूरदर्शी और विकास–केंद्रित दस्तावेज़ के रूप में सामने आता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार अल्पकालिक राहत के साथ–साथ दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन पर भी ध्यान दे रही है। अवसंरचना, कृषि, सामाजिक क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था और उद्योग – सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश दिखाई देती है।

यदि घोषित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है और निजी क्षेत्र भी सक्रिय भूमिका निभाता है, तो यह बजट भारत को तेज़, समावेशी और टिकाऊ विकास की दिशा में आगे ले जा सकता है। विकसित भारत का सपना केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि निरंतर नीति–सुधार, निवेश और जनभागीदारी से ही साकार होगा और यह बजट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ❑❑

ऑपरेशन सिंदूर के बाद 15 प्रतिशत बढ़ा रक्षा बजट

आम बजट सरकार द्वारा वर्ष भर किए जाने वाले आय–व्यय का लेखा–जोखा तो होता ही है भविष्य की रणनीति का संकेतक भी होता है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ हुए आवंटन से यह साफ संदेश मिलता है कि दो तरफा खतरों को देखते हुए सैन्य तैयारी और आधुनिकीकरण पर सरकार का फोकस आगे भी बना रहेगा। यह सीमाओं पर खासकर पाकिस्तान और चीन की ओर से खड़ी की जाने वाली नई चुनौतियों से निपटने की तैयारी को दिखाता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने नौ वें बजट में कोई लोक लुभावना वादे नहीं किए। यह जोखिम भरा परंतु सरकार के नजरिए से संतुलित बजट है। सरकार ने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समावेशी विकास पर जोर देना जारी रखा है। इसके लिए सुरक्षा पर खासा ध्यान दिया गया है और बजट में वित्त वर्ष 2026–27 के लिए 7.85 लाख करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले रक्षा बजट में लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कैपिटल खर्च करीब 22 प्रतिशत बड़ा है। कैपिटल खर्च का मतलब वह रकम जो सैन्य उपकरणों की खरीद, आधुनिकीकरण और इससे जुड़ी चीजों पर खर्च होती है। इस बार भी बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। रक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद का 1.99 प्रतिशत और कुल बजट का 14.67 प्रतिशत है। इस बार रक्षा का कुल बजट 7.85 लाख करोड रुपए है जबकि पिछले साल यह 6.81 लाख करोड रुपए ही था। बजट में पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड रुपए का प्रावधान है वही रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 17250 करोड रुपए दिए गए हैं। तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए1.85 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है जो पिछले साल की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। बजट में हुई वृद्धि से हमारी सैन्य क्षमता और अधिक सशक्त होकर उभरेगी।

दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही देश 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। भारत की कोशिश पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की है, ताकि देश शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सके।

– शिवनंदन लाल

बजट में गृह मंत्रालय का आवंटन बढ़ाकर देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर अतिरिक्त जोर दिया गया है। घुसपैठ रोकने और ऑपरेशन सिंदूर के बाद संदिग्ध ड्रोन को गिराने के लिए बॉर्डर पर एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाये जा रहे हैं जो मजबूत सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश की तीनों सेनाओं को और अधिक सशक्त बनाने का काम पिछले कई सालों से निरंतर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेष रूप से स्वदेशी तकनीक से विकसित साजो सामान पर सरकार का जोर रहा है। हालांकि निजी उद्योगों को भी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से साइन उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया है, और इसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिले हैं। वर्तमान बजट इस पर ध्यान केंद्रित करता है और व्यापक परीक्षण व प्रमाण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी स्वतंत्र निकाय की स्थापना आदि का भी प्रस्ताव करता है। हमारे रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिओस्पेशियल सिस्टम और ड्रोन पर भी विशेष रूप से बोल दिये जाने की बात शामिल है।

रक्षा बजट के साथ–साथ देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की चौकसी को और मजबूत करने के लिए बजट में गृह मंत्रालय को भी 255233 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। यह रकम पिछले वर्ष की तुलना में 22023 करोड रुपए अधिक है। सरकार का मकसद आतंकी हमले पर रोक सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकना और समय पर सटीक खुफिया जानकारी हासिल करना है।

गृह मंत्रालय के कुल बजट में से 173802 करोड रुपए पुलिस मद में दिए गए हैं इससे सीआरपीएफ बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को और अधिक मजबूत किया जाएगा। बजट में कहा गया है कि पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती सीमाओं पर फेसिंग, एंटी ड्रोन सिस्टम और आधुनिक निगरानी उपकरण लगाए जाएंगे। नक्सलवाद खत्म करने में अहम भूमिका निभा रही सीआरपीएफ को 38517 करोड रुपए मिले हैं जबकि बीएसएफ को 29567 करोड रुपए दिए गए हैं।

बजट में गृह मंत्रालय का आवंटन बढ़ाकर देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर अतिरिक्त जोर दिया गया है। घुसपैठ रोकने और ऑपरेशन सिंदूर के बाद संदिग्ध ड्रोन को गिराने के लिए बॉर्डर पर एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाये जा रहे हैं जो मजबूत सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व के क्षेत्र के लिए भी बुनियादी ढांचे के विकास सड़कों और नए हवाई अड्डों के निर्माण पर ध्यान देने की बात कही गई है जो कि भारतीय रक्षा बलों को मजबूत करने में सहायक कदम साबित होगा। चीन के साथ गाहे–बगाहे हो रही झारखंड को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा और सुगम सड़कें समय की मांग है।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के बाद निरपेक्ष रूप से तीसरा सबसे बड़ा रक्षा सामग्री पर खर्च करने वाला देश है। फिर भी चीन और भारत के रक्षा खर्च में लगभग चार गुना का अंतर है। यदि भारत को चीन के विपरीत डटकर खड़ा होना है तो हमें भारतीय रक्षा पर और अधिक खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है। रक्षा संबंधी स्थाई समिति ने भी अपनी सिफारिश में कहा था कि सशस्त्र बलों की पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय को जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का लगभग तीन प्रतिशत हिस्सा निश्चित रूप से आवंटित किया जाना चाहिए।

केंद्र की राजग सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। वर्ष 2017 में भारत का रक्षा बजट केवल 2.74 लाख करोड रुपए था। वित्त वर्ष 2026–27 में इसे लगभग तीन गुना बढ़ाया गया है। वर्षवार देखें तो वर्ष 2023–24 में रक्षा बजट 5.93 लाख करोड रुपए वर्ष 2024–25 में 6.31 लाख करोड रुपए वर्ष 2025–26 में 6.81 लाख करोड रुपए और अब वर्ष 2026–27 के लिए 7.85 लाख करोड रुपए आवंटित किए गए हैं।

कुल मिलाकर रक्षा बजट के लिए और अधिक आवंटन की जरूरत है और आवंटन को बढ़ाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विस्तार की आवश्यकता है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही देश 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। भारत की कोशिश पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की है, ताकि देश शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि तब भारत एशिया के साथ–साथ विश्व स्तर पर खुद को प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने में पूर्णतया सक्षम होगा। ❑❑

पर्यटन को मिलेगी मजबूती

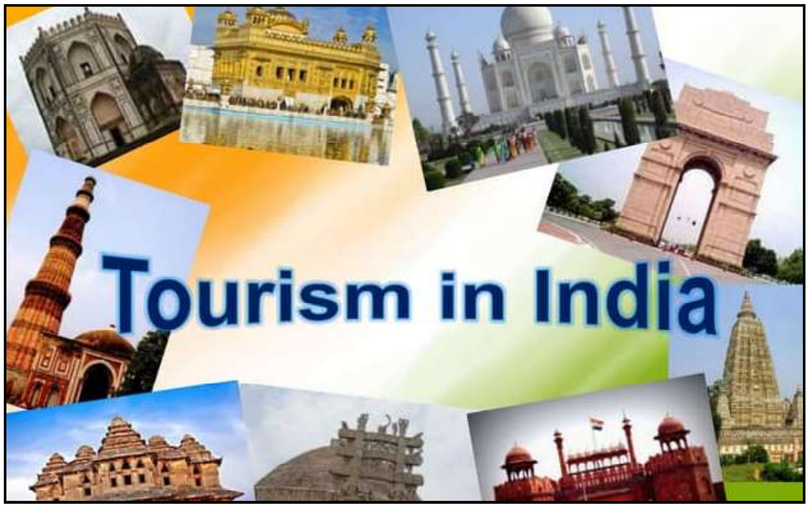

विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों से ओतप्रोत भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति विश्व में अद्वितीय है। विश्व के सात आश्चर्यों में से एक ताजमहल भारत में ही है तो सर्दियों की सतरंगी संस्कृति की विभिन्न कलाकृतियों से सुसज्जित भारत के अध्यात्मिक दर्शन को इंगित करने वाले काशी, अयोध्या, मथुरा आदि मंदिरों की शृंखलाएं भी भारत की समृद्ध एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। हिमालय की पर्वतमालाओं के मध्य बसे राज्यों के इलाके बेहद समृद्ध पर्यावरणीय दृश्य में समाहित हैं तो समुद्र तटीय प्राकृतिक धरोहरों के स्थल भी अत्यंत रमणीय हैं। हर वर्ष लाखों की संख्या में देसी विदेशी पर्यटक विभिन्न ऋतु के मौसम जलवायु भौगोलिक क्षेत्र और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए अतुल्य भारत के इन स्थलों का भ्रमण करते हैं। भारत में पर्यटन उद्योग का स्वरूप लगातार बढ़ रहा है। यूनेस्को द्वारा भारत के 36 सांस्कृतिक साथ प्राकृतिक और एक मिश्रित कुल मिलाकर 44 स्थलों को अब तक विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है। आम बजट 2026–27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरातात्विक महत्व की 15 साइट्स को कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थान समेत सभी अहम जगहों के बारे में जानकारी को डिजिटल स्वरूप देने के लिए "राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड" बनाने का भी प्रस्ताव रखा है।

बजट में लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, सारनाथ जैसे प्राचीन और पुरातात्विक महत्व के स्थान को विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इससे पर्यटन को गति मिलेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होंगे।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

केंद्रीय वित्त मंत्री ने पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के बजट में इस वर्ष 10.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए मंत्रालय का बजट पिछले साल के बजट के मुकाबले 346.64 करोड रुपए बढ़ाया गया है। पिछले वित्त वर्ष के लिए पर्यावरण मंत्रालय को 3412.82 करोड रुपए था जो इस साल बढ़कर 3759.46 करोड रुपए कर दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी बजट में वृद्धि करते हुए इसे 1307 करोड रुपए दिया गया है।

बजट में पुरातात्विक महत्व की जगहों को कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में परिस्थितिकीय तौर पर टिकाऊ पर्वतीय मार्गो को विकसित करने और एक राष्ट्रीय अतिथि सत्कार संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हॉस्पिटैलिटी) बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव के मुताबिक आने वाले दिनों में लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, आदिचनल्लूर, सारनाथ, लेह पैलेस समेत पुरातात्विक महत्व के 15 स्थल कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेंगे।

बजट 2026–27 में वित्तमंत्री ने सभी सेक्टर में विकास और योजनाओं को मूर्त रेप देने का प्रावधानकिया तो पर्यटन क्षेत्र को भी देश की समग्र अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र में से एक के रूप में रेखांकित किया है।पर्यटन के क्षेत्र में नौकरियां और उद्यमिता के बड़े अवसर हैं और कई राज्यों की तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अधिक भागीदारी भी है। यही कारण है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार बजट आवंटन बढ़ाया जाता रहा है। अगर पिछले 3 सालों का आंकड़ा देखें तो 2024–25 में इस क्षेत्र को 2219.7 करोड रुपए मिले थे जबकि अगले वर्ष 2025–26 में इसे बढ़ाकर 3412.82 करोड रुपए कर दिया गया था। इस बार इसमें 346.64 करोड़ की वृद्धि करते हुएकल 3759.46 करोड रुपए के आवंटन का प्रावधान किया गया है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2014 में केंद्र में राजग की सरकार बनने के बाद तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राईव लॉन्च कर पर्यटन मंत्रालय ने 2014–15 में ही प्रसाद स्कीम शुरू की थी। घरेलू पर्यटन का विकास काफी हद तक तीर्थ पर्यटन पर निर्भर है। इसीलिए बजट आवंटन में सभी धर्म के तीर्थ स्थलों के समग्र विकास को गंभीरता से लिया गया है। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से ही पर्यटन विकास के लिए विशेष पैकेज लाती रही है इस बजट में भीइसे आगे बढ़ने का प्रस्ताव किया गया है जो पूर्वोत्तर राज्यों की आधारभूत संरचना को मजबूत करेगा। इसके तहत पर्यटन के सभी पहलुओं को दृष्टिगत करते हुए एक जिला एक उत्पाद योजना की उत्पादों हस्तशिल्प और राज्यों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की राजधानी में यूनिटी मॉल की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता रहा है।

वेस्टलैंड बेहतरीन पारिस्थितिकी तंत्र के दो तक हैं जो जैव विविधता को बढ़ाते हैं बजट में स्थिति की तंत्र और पर्यावरण को दुरुस्त करने की पहल भी प्रशंसनीय है। बुनियादी ढांचे पर विकास के लिए पर्याप्त रस का आवंटन हुआ है इसमें विशेष रूप से रेलवे को अब तक का सर्वाधिक 2 लाख 78000 करोड रुपए दिए गए हैं। इस बजट में रेलवे की बड़ी घोषणा अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर की तरह अन्य साथ हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की की गई है। इसमें से एक हाई स्पीड कॉरिडोर दिल्ली से प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र बनारस को भी कनेक्ट करेगा। इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से बनारस के बीच का सफर का समय घटकर मात्र 3 घंटे 50 मिनट का हो जाएगा। इससे काशी जाने वाले लोगों को सुविधा और सहूलियत बढ़ेगी। यात्रियों के सुरक्षा के लिए भी ध्यान रखा गया है। रेलवे के बजट में सुरक्षा के लिए 1 लाख 20 हजार करोड रुपए आवंटित किए गए हैं जिसमें कवच लगाना अहम हैं। इसके साथ ही पुराने रेलवे ट्रैक की जगह नए ट्रैक बिछाना सिग्नल सिस्टम को और अधिक आधुनिक और एडवांस बनाने की भी बात कही गई है। इन सब गतिविधियों से देश के पर्यटन को मजबूती मिलेगी।

विकास के दृष्टिकोण से भी पर्यटन का क्षेत्र काफी उर्वर है। इस क्षेत्र में रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं जिनके लिए और भी अच्छे काम किए जाने की आवश्यकता है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े होटल इंडस्ट्रीज को भी बजट से काफी उम्मीदें थी हालांकि उन्हें कोई बड़ी राहत नहीं मिली है लेकिन सरकार ने जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाकर उन्हें पहले ही रत दिया है। देश में पर्यटन बोर्ड बनाने की काफी दिनों से मांग चल रही है। पर्यटन इकाइयों को चलाने के लिए विभिन्न तरह के अनुज्ञा शुल्कों में कमी और छूट की मांग भी उठाई जाती रही है।पिछले बजट में दी गई छूट बड़े होटलों तक सिमट कर रह गई थी। उसका लाभ छोटे होटलों को नहीं मिल सका था। उम्मीद थी कि इस बजट में छोटे होटलों को भी फायदा पहुंचेगा।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यटन के मामलों में विभिन्न एनओसी और क्लीयरेंस के लिए अगर सिंगल विंडो सिस्टम लागू होता तो यह उपलब्धि होती। वीजा से लेकर यात्रा ठहरने और घूमने आज के क्लेरेंस एक साथ मिल जाए तो पर्यटन को और गति मिल सकती है। विश्व पटेल पर देखें तो कई देशों में पर्यटन का उनके सकल घरेलू उत्पाद में बड़ा योगदान है। फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, इटली, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान नेपाल, म्यामार जैसे देश पर्यटन उद्योग के रूप में स्थापित हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अन्य उद्योगों की तुलना में पर्यटन क्षेत्र में कम विनियोग से ज्यादा रोजगार सृजन होता है। विदेशी मुद्रा की आमदनी के साथ–साथ श्रम को बेहतर रोजगार मिलता है। कई देशों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ईवीजा के साथ बीजा आनअराइवल की सुविधा दी हुई है। भारत में ई–वीजा की शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी कुछ देशों को ही ईवीजा अराइवल की सुविधा है। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यटन संगठन सदस्य देशों को उत्साहित करता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित होने पर विदेशी पर्यटकों का आकर्षण बढ़ता है। बजट में लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, सारनाथ जैसे प्राचीन और पुरातात्विक महत्व के स्थान को विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इससे पर्यटन को गति मिलेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होंगे। ❑❑

बजट से मजबूत होगी आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद

वित्त वर्ष 2026–27 के बजट में तीन तरह के कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है, वह देश की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही आर्थिक उथल–पुथल के कारण यह कदम उठाना जरूरी था। वर्तमान में टैरिफ के माध्यम से अमेरिका ने व्यापार के क्षेत्र में अंकुश लगाने की कोशिश की है। इस कारण आवश्यक हो गया था कि उत्पादकता बढ़ाकर वैश्विक उथल–पुथल के बीच आर्थिक विकास में संतुलन बनाकर विकास को गति प्रदान की जाए। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने वाला काम है। इसी के साथ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण भी आवश्यक है। जिससे कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को चलाकर एमएसएमई के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया जाएगा। देश में 2016 में जब स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी तब 500 स्टार्टअप थे। वर्ष 2025 में लगभग 44000 स्टार्टअप देश में प्रारंभ किए गए। आज लगभग 2 लाख स्टार्टअप देश में काम कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि यदि एक स्टार्टअप से 10 लोगों को रोजगार मिलता है तो 2 लाख स्टार्टअप से लगभग 2 करोड लोगों को देश में रोजगार प्राप्त होगा जो आत्मनिर्भर अभियान की ओर एक सराहनीय कदम है। किसानों को प्रशिक्षण देकर उनका कौशल बढ़ाने का कार्य करने की भी योजना बनाई गई है जिससे किसान वैज्ञानिक खेती कर अपनी आय को दो गुना करने के लिए अग्रसर हो। महिलाओं को स्वसहत्ता समूह के माध्यम से रोजगार देने की कोशिश की गई है जिससे भारतीय महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके।

सी–मार्ट की एक नयी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसका सीधा अर्थ है,कि स्व सहायता समूह से बनाए गए उत्पादों को सी–मार्ट के माध्यम से बेचा जाएगा अर्थात उनके मार्केटिंग के लिए एक उपयुक्त स्थान दिया जाएगा। इससे स्वदेशी प्रोडक्ट को बाजार मिलेगा और आत्मनिर्भर बनने की ओर हमारा प्रयास सफल होगा। युवाओं को तकनीकी की पढ़ाई से जोड़ा जाएगा। शिक्षा संस्थानों में स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे हमारा युवा

विकास और कल्याण के लिए जो तीन कर्तव्य भारत सरकार ने अपने बजट में उल्लेख किए हैं इसका सीधा मतलब है, कि किसान, महिला, युवा और गरीब का कल्याण ही सर्वोपरि है।

– डॉ. जयप्रकाश मिश्र

आईटी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, अपने हुनर को प्रदर्शित कर पाएगा।

गरीब परिवारों को गरीबी से निकालने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की प्रतिबद्धता है। बजट में कहा गया है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 22 करोड लोगों को गरीबी भी उन्मूलन की योजनाएं चला कर गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया है। वर्ष 2026 के प्रस्तुत बजट में आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योजनाएं बनाने का प्रावधान किया गया है। इस बजटीय प्रावधान से विकास के मुख्य धारा से जो वंचित समुदाय है उसको जोड़ने का प्रयास किया गया है।

इस तरह विकास के जो चार स्तम्भ पिछले बजट में केंद्र बिंदु थे। उनको आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। जिसे 'ज्ञान' कहा गया था।

गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी इन चारों वर्गों को यदि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या इस सीमा में आ जाती है।

वर्ष 2026 के बजट में ऐसे कदम उठाने का प्रयास किया गया है कि जिससे लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, निर्यात को बढ़ाया जा सके और योजनाओं का सरलीकरण किया जा सके, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सके। मेडिकल के क्षेत्र में भी स्किल को विकसित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी सुधार किया जा सके। हमारे प्राचीनतम आयुर्वेद शिक्षा के क्षेत्र में हम पुनः अपने को प्रतिस्थापित कर सकें, इसके लिए भी योजना बनाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी अनेक तरह के सुधार, एक्सप्रेस वे आदि का बजट प्रावधान किया गया है। देश की सुरक्षा के लिए 15 प्रतिशत बजट का जो प्रावधान किया गया है वह इसलिए के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में हालात उथल–पुथल के हैं। इसलिए एमएसएमई के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करने हेतु 10000 करोड़ के ग्रोथ फंड का प्रावधान किया गया है, जिससे 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टर को पुनर्जीवित करने की योजना साकार रूप ले सके। आत्मनिर्भर भारत निधि में 2000 करोड रुपए का टॉप अप का प्रावधान किया गया है जिससे शहरों में आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा।

वर्ष 2026 के बजट में ऐसे कदम उठाने का प्रयास किया गया है कि जिससे लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, निर्यात को बढ़ाया जा सके और योजनाओं का सरलीकरण किया जा सके, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सके।

भारत विस्तार नाम से डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में नई पहल करने की शुरुआत की जा रही है। किसानों को खेती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगी और इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ा जाएगा ताकि किसान सही समय पर सही जानकारी प्राप्त कर सकें। किसानों को खेती के साथ बाजार बीज और उर्वरक संबंधी सलाह भी मिल सकेगी। यह प्लेटफॉर्म किसान को समस्याओं से निजात दिलायेगी, क्योंकि किसान बीज और उर्वरक के लिए वास्तव में मंडियों के, बीज संस्थानों के चक्कर लगाता रहता है।

आर्थिक विकास को गति देने के लिए छह क्षेत्रों पर बजट में फोकस किया गया है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में तेजी, विरासत के औद्योगिक क्षेत्र का कायाकल्प, चैंपियन एमएसएमई का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन, ऊर्जा सुरक्षा में स्थायित्व, सिटी इकोनामिक जोन बनाना आदि। यह सभी छह क्षेत्र अर्थव्यवस्था की धुरी है।

जैसा कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा में ही कहा गया है कि व्यक्ति की आय में विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है। इस बजट में आयकर रिटर्न भरते समय विदेश से प्राप्त संपत्ति को भी जोड़ने का प्रावधान किया गया है। विदेशी टूर व पढ़ाई पर टीसीएस घटाया गया है। उसे 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत किया गया है। हमारे देश के प्रवासी भारतीय प्रतिभाओं को भी इस

बजट में राहत देने का काम किया गया है। भारत में प्रॉपर्टी बेचने पर या खरीदने पर टिन नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि पैन आधारित चालान से ही टीडीएस जमा किया जा सकेगा। विदेशी प्रतिभाओं को राहत के लिए बजट में टैक्स छूट भी दी गई है।

प्रतिभाओं को राहत देने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वह अपनी आय का अधिकांश भाग विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय बैंकों में जमा करें या भारत में निवेश करें। जिससे भारत में विदेशी मुद्रा के भंडार मैं वृद्धि होगी और अंतरराष्ट्रीय भुगतानों के लिए हमें विदेशी मुद्रा को क्रय नहीं करना पड़ेगा। इससे हमारा रुपया भी मजबूत होगा। ट्रंप टैरिफ से भी काफी हद तक राहत मिलेगी। प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार संरचना और घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है जो ज्यादा टिकाऊ है। प्रतिस्पर्धात्मक लागत संरचना और घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने को प्राथमिकता दी गई है जो ज्यादा टिकाऊ है। मैन्युफैक्चरिंग सुधारो सेमीकंडक्टर जैसी नई तकनीकी के लिए किए गए उपाय एमएसएमई को मदद करेगा।

कुल मिलाकर भारत सरकार का फोकस युवा गरीब किसान महिलाओं पर है कि उनके विकास के लिए हम किस तरह की योजनाएं बना करके भारत को 2047 में किस तरह से विकसित भारत की ओर ले जा सकते हैं। हमारे बुद्धिजीवियों, योजनाकारों, नवाचार में लगे हुए लोगों का यह सपना है कि भारत पुनः विश्व गुरु कैसे बनें?

सार रूप में हम कह सकते हैं कि भारत सरकार निरंतर बुनियादी ढांचे में परिवर्तन तकनीकी के क्षेत्र में परिवर्तन प्राथमिक और द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में प्रगति के साथ ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और मानव कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर राष्ट्र कल्याण के लिए तत्पर है। हम देश के नागरिकों को भी आत्मबोध, कर्तव्य बोध और राष्ट्रबोध का जज्बा लेकर समर्पित भाव से अपने को संलग्न करना होगा तभी हम विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा कर सकते हैं।

सार रूप में हम कह सकते हैं कि भारत सरकार निरंतर बुनियादी ढांचे में परिवर्तन तकनीकी के क्षेत्र में परिवर्तन प्राथमिक और द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में प्रगति के साथ ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और मानव कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर राष्ट्र कल्याण के लिए तत्पर है।

यहां हम संदर्भ के लिए एक बात और बताना चाहेंगे की 2025 में जो यूरोपियन यूनियन से भारत ने समझौता किया है उसमें 27 देश हैं जिसमें 17 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में सहयोग का आश्वासन दिया है। 2025 के डाटा बताते हैं कि यूरोपियन संघ से जो हमारी व्यापार की डील हुई थी उसमें 75.85 अरब डॉलर के हमारे निर्यात हैं जबकि आयत हमारे 60.68 अरब डॉलर के हैं। कहने का आशय है कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के साथ विदेशी व्यापार में भी निर्यातों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे विदेशी मुद्रा के भंडार हमें मिल सकें और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

भारत और अमेरिका का टैरिफ वार कम होने की ओर है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के आयात कम हो जाएंगे और निर्यात बढ़ जाएंगे। यह यूरोपीय यूनियन और भारत सरकार के समझौते के कारण ट्रंप दबाव महसूस कर रहे हैं। दूसरा कारण भारत में किसान महिला युवा एवं गरीब पर केंद्रित जो देश की सरकार और प्रदेश की सरकारें जो संकल्प पत्र ले आए हैं। इस संकल्प पत्र का नतीजा है कि भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या इसमें आती है, जिसे भारत सरकार ने 'ज्ञान' की संज्ञा प्रदान की है। मैं इसे सरल भाषा में 'किमयुग', (किसान, महिला, युवा और गरीब) कहना चाहूंगा!

'किमयुग' के लिए जिस तरह की योजनाएं धरातल पर दृष्टिगोचर हो रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की ग्रोथ रेट को मजबूती देने का काम भी इन चारों वर्गों ने किया है। परिणामस्वरूप भारत का ग्रोथ रेट कम नहीं हुआ और आगामी वर्षों में कौशल विकास के जो कार्यक्रम इन वर्गों के लिए चलाए जा रहे हैं उससे भारत का वर्कफोर्स और अधिक कौशल से विकसित होगा, और यह कौशल पूर्ण वर्ग, जब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अपनी कौशल पूर्ण सेवाएं प्रदान करेगा तो भारत विकसित होगा। दुनिया का हर देश यह जानता है कि भारत के युवा कर्मठ है, लग्नशील हैं, और ब्रेन पावर से परिपूर्ण है। यदि विकसित देश यह सोच रहे हैं कि भारत के युवाओं पर हम अपने तरह की नीतियां थोपेंगे, तो भारत का युवा हतोत्साहित होकर हमारी शर्तों पर काम करेगा तो यह विकसित देशों की भूल है। भारत का ब्रेन पावर भारत के लिए काम करेगा। और यदि ऐसा हुआ तो भारत का ब्रेन पावर दुनिया में विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनाने में अपना सहयोग करेगा। तभी विकसित भारत की संकल्पना अपने टारगेट के पहले ही पूरी होगी। ❑❑

रेल सफर सुहावना करने का वादा!

अगर कहा जाये कि भारतीय रेलवे देश के लोगों की जीवन रेखा है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। बजट 2026–27 में रेलवे को अब तक का सर्वाधिक 2 लाख 78 हजार करोड़ रूपये आवंटित किये गये है। प्रतिदिन लगभग ढ़ाई करोड़ लोग रेलयात्राा करते हैं वहीं भारत में उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में रेलवे की मुख्य भूमिका रहती है। भारत में इन उत्पादों की गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से 7 नए हाई स्पीड रेल कोरिडोर बनाए जाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। यह कोरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बैंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बैंगलोर, दिल्ली से वाराणसी एवं वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच विकसित किए जाएंगे। यह क्षेत्र विकास के नए केंद्र बन जाएंगे।

भारत को विश्व में लाजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने के लिए इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया जा रहा है ताकि भारत में ही कंटेनर के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।

दिनांक एक फरवरी 2026 को, रविवार के दिन, भारत की वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने भारतीय संसद में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में की गई घोषणाओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर घटित हो रही उथल–पुथल से भारत को बचाने की पुरजोर कोशिश की गई दिखती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा अपने द्वितीय कार्यकाल में वर्ष 2025 के दौरान पूरे वर्षभर लगातार कई देशों के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर टैरिफ की घोषणाएं की जाती रहीं एवं इसके विरोध स्वरूप कुछ देशों ने अमरीका से इन देशों से होने वाले निर्यात पर प्रतिकारी टैरिफ लगाने की घोषणाएं की जाती रहीं। चीन ने तो प्रतिशोध में अमेरिका को दुर्लभ खनिज पदार्थों की आपूर्ति ही रोक दी थी। हालांकि इसके पूर्व अमेरिका ने भी चीन के सेमीकंडक्टर एवं चिप्स की आपूर्ति को प्रभावित करने का प्रयास किया था। कुल मिलाकर, कुछ देश तो आपस में विभिन्न वस्तुओं के आयात एवं निर्यात को रोकने के प्रयत्न करते रहे। इन सभी घोषणाओं से वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में माहौल विपरीत रूप से प्रभावित होता रहा। ट्रम्प प्रशासन ने भारत

बजट 2026–27 में 7 नए हाई स्पीड रेल कोरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा से यह क्षेत्र विकास के नए केंद्र बन जाएंगे।

– प्रहलाद सबनानी

से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर भी 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, जो अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ में संभवतः आज अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है।

इस वित्तीय वर्ष के बजट में तीन कर्तव्यों को ध्यान में रखा गया है। (1) विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए भारत की आर्थिक विकास दर को और अधिक तेज किया जाय ताकि भारत को वैश्विक स्तर पर चल रही उथल पुथल से बचाया जा सके; (2) भारतीय युवाओं में कौशल का विकास करना ताकि तकनीकी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तनों के लिए वे अपने आप को तैयार कर सकें; (3) देश में समावेशी विकास हो सके एवं भारत के संसाधनों का उपयोग समस्त नागरिकों की भलाई में किया जा सके और कोई भी नागरिक, नगर एवं राज्य आर्थिक विकास की धारा से बाहर नहीं रहे।

वैश्विक स्तर पर उक्त वर्णित परिस्थितियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रही। परंतु, भारत की विकास दर की इस गति को आगामी वर्षों में भी बनाए रखने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। भारत आज दुर्लभ खनिज पदार्थों तथा सेमीकंडक्टर एवं चिप्स का भारी मात्रा आयात करता है। चिप्स को तो आज के उत्पादों के निर्माण में तेल की भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। इन दोनों पदार्थों पर चीन एवं अमेरिका का लगभग पूर्णतः एकाधिकार है। भारत अपने आप को इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। इस दृष्टि से बजट में भारत में ही दुर्लभ खनिज पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ओड़िसा, केरल, तमिलनाडु एवं आन्ध्र प्रदेश स्थित खदानों में से कच्चे माल को निकालकर इसे संसाधित करते हुए भारत में ही दुर्लभ खनिज पदार्थों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में उक्त चारों राज्यों में एक कोरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार, भारत में ही सेमीकंडक्टर एवं चिप्स के निर्माण हेतु विनिर्माण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में कई उपायों की घोषणा की गई है एवं इस हेतु 40,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही, इसके लिए बजट में सेमीकंडकर मिशन 2.0 को लागू करने की भी घोषणा की गई है। इससे कंपनियों को भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण इकाईयों को स्थापित करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

हाल ही में भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं, इन समझौतों में 27 विकसित देशों के समूह, यूरोपीयन यूनियन से किया गया मुक्त व्यापार समझौता भी शामिल है। इसे "मदर आफ ऑल डील्स" कहा जा रहा है क्योंकि यह समझौता 28 देशों (27+1) के बीच एक साथ किया गया सबसे बड़ा समझौता है। इन मुक्त व्यापार समझौतों से भारत में वस्त्र एवं परिधान उद्योग, समुद्रीय पदार्थ उद्योग, चमड़ा उद्योग, खिलौना उद्योग एवं जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग, आदि को सबसे अधिक लाभ होने जा रहा है। इन उद्योगों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम भारी मात्रा में कार्यरत हैं। भारत में उक्त वर्णित पदार्थों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को रियायतें देने का प्रयास किया गया है ताकि उक्त वर्णित उत्पादों की मांग में होने वाली वृद्धि को पूर्ण किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई फंड भी बनाया गया है। टेक्स्टायल उद्योग को भी विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारत में निर्मित वस्त्र एवं परिधानों को विश्व के पटल पर रखा जा सके। साथ ही, बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की व्यवस्था, बायोफार्मा शक्ति के रूप में, इस बजट में की गई है। इससे भारतीय दवा उद्योग को विश्व के मानचित्र पर और आगे ले जाने में सहायता मिलेगी।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में विकसित आधारभूत संरचना की अहम भूमिका रहती है। इस बजट के माध्यम से भारत में आधारभूत संरचना को विकसित करने के उद्देश्य से पूंजीगत खर्चों में भारी भरकम वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूंजीगत खर्चों के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी, इसे वर्ष 2026–27 के बजट में बढ़ाकर 12.20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2014–15 के बजट में पूंजीगत खर्चों के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था। पिछले 13 वर्षों में पूंजीगत खर्चों में 6 गुना से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। पूंजीगत खर्चों में वृद्धि से कई क्षेत्रों में सरकारी निवेश भी बढ़ता है एवं इससे अंततः रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होते हैं। बल्कि, अब तो सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी अपने पूंजी निवेश को बढ़ाना होगा। क्योंकि, सरकार के पूंजीगत खर्चों में अतुलनीय वृद्धि से देश में ही विभिन्न उत्पादों के निर्माण में तेज गति से वृद्धि होगी और वर्तमान विनिर्माण इकाईयों की उत्पादन क्षमता का उपयोग 80 प्रतिशत से ऊपर निकल जाएगा, जो वर्तमान में लगभग 75 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचा है, इससे नई उत्पादन इकाईयों को स्थापित करना आवश्यक होगा। अतः भारत में अब निजी क्षेत्र में भी निवेश बढ़ेगा, इसमें विदेशी निवेश भी शामिल है।

(शेष पृष्ठ 23 पर ...)

राज्यों की आर्थिकी और केंद्र की भूमिका

संसद के मौजूदा बजट सत्र के दौरान दो प्रमुख रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। पहली, वैश्विक भू–राजनीतिक उथल–पुथल और दुनिया के देशों के साथ लगातार हो रहे मुक्त व्यापार समझौतों के दरमियान केंद्रीय बजट 2026–27 और दूसरी बहुप्रतीक्षित 16वीं केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार की अनुशंसा जो वर्ष 2026–27 से अगले 5 वर्ष तक के लिए प्रभावी रहेगी। दोनों रिपोर्ट का देश के आर्थिक विकास की तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों जरूरतों पर व्यापक असर होगा और आने वाले समय में देश और राज्यों के आर्थिक विकास की रूपरेखा इनमें प्रस्तुत आंकड़ों से बहुत हद तक प्रभावित होगी।

लगातार रिकॉर्ड नवीं बार देश का आम बजट प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि केंद्र ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली है।नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्रीय करों में से 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को दिया जाए। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी की यह सिफारिश एक अप्रैल से अगले पांच वर्षों के लिए अनुमन्य है। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए वित्त आयोग अनुदान के रूप में राज्यों को देने के लिए 1.4 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया है। मालूम हो की 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश भी हु–ब–हू ऐसी ही थी, लेकिन केंद्र की ओर से राज्यों को इसके तहत केवल 34 प्रतिशत के बराबर की रकम ही दी गई, जिसे वित्त वर्ष 2027 में बढ़ाकर 34.6 प्रतिशत दिए जाने का वादा किया गया है।

आज पूरी दुनिया जिस तरह के वैश्विक भू राजनीतिक उथल–पुथल के दौर से गुजर रही है और इस कारण देश के सामने जो कठिनाइयां खड़ी हो रही हैं, वित्त मंत्री ने अपने आम बजट के जरिए उससे बाहर निकलने का एक रोडमैप पेश किया है। वित्त मंत्री ने उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हुए आर्थिक विकास तेज करने, लोगों को सक्षम साझीदार

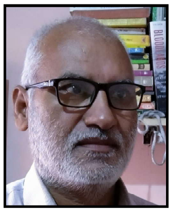

आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है फिर भी हर वर्ष केंद्रीय बजट से नई उम्मीद बनी रहती है। इसका प्रमुख कारण तात्कालिक समस्याओं को लेकर सरकार से की जाने वाली अपेक्षाएं हैं।

–अनिल तिवारी

बनाकर उनकी आकांक्षाएं पूरी करने और सबका साथ–सबका विकास की सोच के साथ सभी को अवसर मुहैया कराने के तीन मुख्य कर्तव्यों की प्रतिबद्धता जताते हुए सात रणनीतिक सेक्टरों में अपेक्षित प्रगति के साथ भारत को अगले स्तर पर ले जाने का वादा किया है। रोजगार की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने आम बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस किया है तथा सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य तय किया है, जोकि अभी तक 20 प्रतिशत का लक्ष्य भी हासिल नहीं किया जा सका है।

पहले करोना संकट के दरमियान केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय सीमा रेखांकित और संकुचित हुई थी,जिसके कारण केंद्र के साथ राज्य की सरकारें भी विकास संबंधी खर्चों को लेकर अमूमन दबाव में थी। और अब दुनिया भर में छिड़े टैरिफ वार की मार, प्रतिक्षण बदलती भू राजनीतिक स्थिति, लगातार बढ़ती आबादी की जरूरतों और बड़े श्रम बल को समुचित रोजगार की आवश्यकता, कृषि क्षेत्र को लेकर असंतोष और पलायन से आने वाली समस्याएं जैसी चिंताएं बनी हुई है। इसका एक प्रमुख कारण राजस्व की कमी और दीर्घकालिक रणनीति का अभाव भी रहा है।

हालांकि बजट में वित्त मंत्री ने अपने राजस्व की चिताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाओं में सामंजस्य से बैठाने की कोशिश की है। भविष्य के भारत को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए उत्पादकता और घरेलू खपत को बढ़ाने की ठोस रणनीति तैयार की है। भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद खपत है। देश की जीडीपी में इसका योगदान 60 के करीब है।पिछले साल के बजट में खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर आयकर माफ कर दिया था। सरकार ने पिछले दिनों जीएसटी दरों को भी तर्कसंगत बनाया है। रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में कटौती करते हुए 0.75 बेसिस प्वाइंट की कमी की है।

आर्थिक सर्वेक्षण के आकलन के हिसाब से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत आत्मनिर्भरता की राह पकड़कर विकासशील देश से विकसित देश की कोटि में शामिल होने के लिए खुद को तैयार करने में जुटा है। प्रधानमंत्री ने बजट के बारे में कहा है कि "यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है जो 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है"।

सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो बजट सरकार के साल भर में किए जाने वाले आय और व्यय की रूपरेखा है परंतु वर्तमान में उठाए गए कदमों का असर आने वाले समय में होने के कारण इसकी घोषणाएं दीर्घकालिक रणनीति को भी रेखांकित करती है। वहीं केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा का केंद्र के साथ–साथ राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर व्यापक प्रभाव होता है और इसके निर्णय 5 वर्षो तक के लिए लागू रहते हैं।

भारत के संघीय ढांचे में केंद्र राज्य के साथ–साथ राज्यों के बीच भी राजकोषीय क्षमता, स्थिति और आर्थिक सामाजिक विकास के स्तर पर काफी असमानता एवं असंतुलन है। कम विकसित राज्यों की स्थिति और भी नाजुक है। राज्य सरकारों के पास राजस्व संग्रह के विकल्प कम है और कर लगाने की उनकी स्वायत्तता अप्रत्यक्ष कर में हुए व्यापक सुधार के तहत जीएसटी के लागू होने के साथ ही बहुत ही कम हो गई है। वहीं कर्ज लेने और उन्हें चुकाने की राज्यों की क्षमता भी केंद्र से कम है जिसके कारण राज्यों की वित्तीय निर्भरता केंद्रीय राजस्व पर ही अधिक रही है। कम विकसित राज्यों की यह निर्भरता और भी अधिक है क्योंकि विकास की जरूरतों को पूरा करने के संसाधन वहां बहुत ही कम है। साथ ही एक अन्य चिंता राज्य सरकारों के खर्चों की गुणवत्ता को लेकर भी बनी रहती है। हालांकि बजट में केंद्र का राज्यों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने को लेकर प्रेरित करना अच्छा कदम है परंतु राज्यों की राजकोषीय स्थिति निराश करती है।

विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच आर्थिक विषमता को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग की स्थापना हर पांच साल पर की जाती है। इसका मुख्य कार्य यह तय करना है कि केंद्र सरकार करों से एकत्र राजस्व को राज्यों के साथ कैसे साझा करेंगी? साथ ही यह भी तय किया जाता है कि उस साझेदारी में किस राज्य की हिस्सेदारी कितनी होगी? इसके पीछे की अवधारणा यह है कि देश के हर कोने में रहने वाले नागरिकों को देश के सकल आर्थिक संसाधनों का लाभ समान रूप से मिले और इसमें आर्थिक संसाधनों की क्षेत्रीय विषमता के कारण आने वाली बड़ी बाधाओ को दूर किया जा सके। पिछले कुछ आयोगों की अनुशंसा में राज्यों के जनसंख्या घनत्व को लेकर राज्यों के बीच काफी मतभेद रहा है। वर्तमान आयोग ने जनसंख्या और जनसंख्या नियंत्रण के राज्यों के प्रयास दोनों का अपने फार्मूले में उपयोग किया है।

16वें वित्त आयोग की सिफारिशों का महत्व इस कारण भी बढ़ गया है कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक विकास की असमानता पहले से काफी अधिक है और यह देश में जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र राज्य के बीच राजस्व बंटवारे का भी मामला है। आयोग ने केंद्र के करों के विभाज्य

हिस्से में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत रखी है। हालांकि कई कारणों से केंद्रीय राजस्व के विभाजित होने वाले हिस्से का आकार ही कम होने से राज्यों की राजकोषीय स्थिति और खराब होगी। इसका प्रमुख कारण पहले से लागू कई तरह के सेस के ऊपर व्यय के नाम पर लगाए जाने वाले अन्य अतिरिक्त सेस हैं।उदाहरण के लिए वर्ष 2018–19 में शेष से लगभग 2.75 लाख करोड रुपए एकत्र हुए जो केंद्र के राज्यों को विभाज्य राजस्व के हिस्से में नहीं गए। अतः केंद्र द्वारा अधिक मात्रा में सेस लगाने से सरकारों के बीच राजकोषीय संतुलन को कम करना और भी मुश्किल हो जाता है। एक और कदम जो कि राज्यों के खर्चे की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है वह है राज्यों को दी जाने वाली रेवेन्यू घाटे की क्षतिपूर्ति। यह एक तरह से खराब राजकोषीय प्रबंधन को पुरस्कृत करने जैसा है। ऐसे राज्य जो अपने कुल राजस्व प्राप्ति के अधिकतम हिस्से के लिए केंद्र पर निर्भर हैं उनकी हिस्सेदारी इन कारणों से नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है फिर भी हर वर्ष केंद्रीय बजट से नई उम्मीद बनी रहती है। इसका प्रमुख कारण तात्कालिक समस्याओं को लेकर सरकार से की जाने वाली अपेक्षाएं हैं। मौजूदा बजट से शेयर बाजार बहुत मायूस है। हमेशा ललचायी नजर से बजट की प्रतीक्षा करने वाला देश के मध्य वर्ग ने बजट को 'बोरिंग' बताया। राजनीतिक दल अपने–अपने चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन तटस्थ होकर बजट के प्रावधानों को देखने भर से महसूस होता है कि यह एक समावेशी बजट है। इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य की चिंता है, उसके भले के लिए प्रयास करने का संकल्प है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए बजटीय प्रावधान भी कमोबेश मुफीद नजर आते हैं। बावजूद, इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक परिपक्वता की जरूरत है। केंद्र को राज्यों के प्रति आर्थिक संसाधन प्रदान करने के रवैया को और सकारात्मक करने की भी जरूरत है, क्योंकि देश के समग्र विकास में राज्यों की बड़ी भूमिका है। वर्तमान में केंद्र–राज्य सामंजस्य बिठाना भी और आसान होना चाहिए तब जबकि अधिकतर राज्यों में समान विचारधारा की सरकारें हो। इन सबके बीच दीर्घकालिक रणनीति के तहत लंबे समय में देश की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर लोगों को रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उनके जीवन की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए बड़े एवं सार्थक कदम उठाने जरूरी है। ❑❑

(पृष्ठ 20 से आगे...)

रेल सफर सुहावना करने...

भारत में मेडिकल टुरिजम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 हब बनाए जाएंगे। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र एवं राज्यों को भी साथ में लिया जाएगा। इससे भारत में उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी एवं अन्य देशों के नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत की ओर आकर्षित होंगे। इसी प्रकार, भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बौद्ध सर्किट का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे अन्य देशों के बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत में धार्मिक पर्यटन हेतु आकर्षित हो सकेंगे। भारत को पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है क्योंकि भारत में समस्त धर्मों का आदर किया जाता है।

पूरे विश्व में ऐनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एवं कॉमिक क्षेत्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाशने एवं इस क्षेत्र को भारत में ही बढ़ाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का निर्णय इस बजट में किया गया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 20 लाख युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। अतः इस हेतु भारत में ही विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्व विद्यालयों में इस क्षेत्र में शिक्षा एवं कौशल प्रदान करने हेतु उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

आयकर की दरों में किसी प्रकार की वृद्धि प्रस्तावित नहीं है। जबकि आयकर के नियमों को सरल बनाया गया है। आय कर की नई योजना के अंतर्गत अब 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य आयकर लगता है। आयकर रिटर्न फाइल करने हेतु समय सीमा को भी बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार, इस संदर्भ में आयकर नियमों को सरल बनाया जा रहा है

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट की कुछ मुख्य विशेषताओं में वित्तीय अनुशासन का अनुपालन किया जाना भी शामिल है। बजटीय घाटे को 4.5 प्रतिशत के अंदर रखने का प्रयास सफल रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजटीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रखने में सफलता हासिल हुई है। जबकि, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी आज बजटीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजटीय घाटे को कम करते हुए इसे 4.3 प्रतिशत तक नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान पूंजीगत खर्चों में 1.1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि भी प्रस्तावित है। ❑❑

(प्रहलाद सबनानी, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर।)

भारतीय अनुभूति के निराले देवता हैं शिव

शिव भारतीय अनुभूति के निराले देवता है। बाकी सब देव हैं, शिव महादेव हैं। शिव वैदिक वनस्पतियों के राजा है, वह अपने मस्तक पर सोम धारण करते हैं। पौराणिक शिव के गले में सांपों की माला है। ऋग्वेद में हुए तीन मुंह के देवता हैं, त्र्यंबकम यजामहे। शिव यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी है। शिव नटराज है, नृत्यावसाने नटराज राजौ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम शिव के उपासक हैं। श्री कृष्ण शिव के दर्शन के लिए तप करते हैं। कालिदास ब्रह्मा–विष्णु–महेश की त्रिमूर्ति में केवल शिव तत्व देखते हैं।

संस्कृति मनुष्यता के सत्कर्मों का शिव सौंदर्य है। यह राष्ट्र की आत्मा भी होती है। एक सुनिश्चित भूमि पर रहने मात्र से राज्य बनता है, राष्ट्र निर्माण का प्रमुख घटक संस्कृति है। संस्कृति का मूलाधार दर्शन है। किसी भी राष्ट्र का दार्शनिक चिंतन ही राष्ट्र जीवन का बीज होता है। भारत में हजारों साल की सांस्कृतिक निरंतर का प्रवाह है। इस सांस्कृतिक विकास को दर्शन और विज्ञान की धाराओं में लगातार मजबूत किया है। हमारी संस्कृति में वही शिव तत्व है जो कण–कण में व्याप्त है। इसका न जन्म होता है और न मृत्यु, यह अजन्मा है। जो क्षणभंगुर है, वह नित्य है, जिसका नाश नहीं होता, वह नित्य है। शिव नित्य है, वह कालों के भी काल 'महाकाल' हैं।

शिव भोलेशंकर भी हैं। शिव हिन्दू दर्शन की निराली अनुभूति है। शिव अधिकांश विश्व के उपास्य हैं और समूची हिन्दूभूमि की आस्था हैं। विश्व के प्राचीनतम् ज्ञान अभिलेख ऋग्वेद में उनका उल्लेख 75 बार हुआ है। ऋषि वशिष्ठ के मन्त्र (ऋ. 7.59.12) में वे त्रयम्बक यानि तीन मुख वाले देव हैं। यही पूरा मंत्र–त्रयम्बक यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्ध्दनम्, उर्वारुकमिव बंधनार्न्मृत्योमुक्षीय मामृतात्, महामृत्युञजय मंत्र के नाम से दुनिया में चर्चित है। प्रार्थना है कि हम तीन मुख वाले सुरभित, कीर्तिवर्ध्दक जगत् पोषक, संरक्षणकर्ता की उपासना करते हैं, वे देव हमें ककड़ी–खरबूजा की तरह मृत्यु बंधन से मुक्ति दें, अमरत्व दें। रुद्र ही शिव

भारत का लोक जीवन शिव अभीप्सु है। शिव और लोकमंगल पर्यायवाची हैं। हिन्दू अनुभूति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रयी है।

– वैदेही

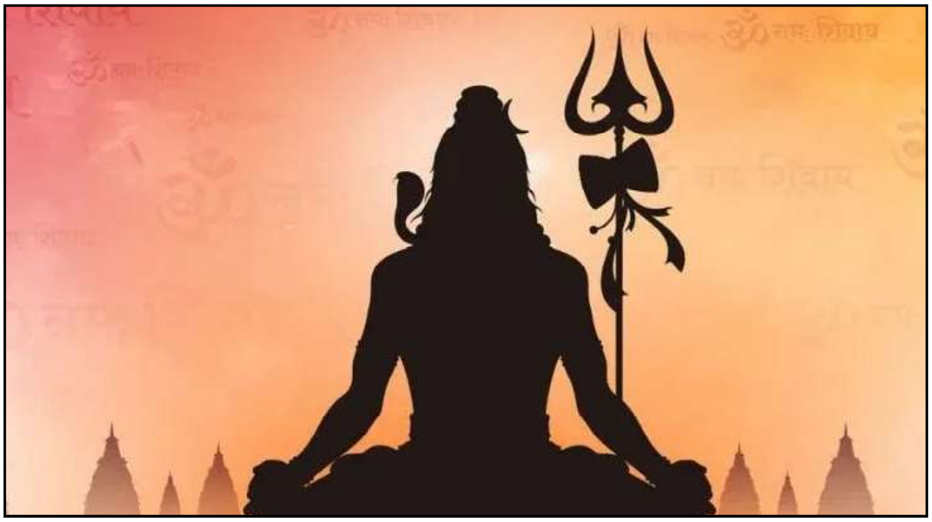

वेद, पुराण और महाभारत कपोल कल्पित कविता नहीं हैं। इनमें इतिहास और विज्ञान के तथ्य हैं। उपनिषद् दर्शन ग्रन्थ है। रुद्र शिव श्वेताश्वतर उपनिषद् में भी हैं – एको रुद्र द्वितीयो नास्ति। यजुर्वेद का 16वां अध्याय रूद्र उपासना पर है। ऋषि, रुद्र का निवास पर्वत की गुहा मे बताते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं।

हैं, शिव ही रुद्र भी हैं– स्तोमं वो अद्य रुद्राय येमि शिवः स्ववां।(ऋ010.92.9) वे जब कर्म फल के कारण रुलाते हैं तो रुद्र जब अनुकम्पा करते हैं तो शिव लोक मंगल के दाता हैं। वशिष्ठ की प्रार्थना है कि हे भरतजनो! शस्त्रधारी क्षिप्रवाण संधानक, अजेय रुद्र की स्तुतियाँ करें। (7.46.1) मार्क्सवादी चिन्तक डॉ. रामविलास शर्मा ने पश्चिम एशिया और ऋग्वेद (पृ. 181–82) में रुद्र उपासना को समूची पश्चिम एशिया में व्यापक बताया है। पिचार्ड के चित्रग्रन्थ में लगभग दूसरी सहस्त्राब्दि ईसापूर्व की एक सीरियायी मुद्रा में वे हाथ में परशु लिए मौसम के देवता हैं। 11वीं सदी ई. पूर्व के एक भग्न ईराकी स्तम्भ में वे सूर्य बिम्ब के नीचे परशु लिए अंकित हैं। वे हित्तियों के विशेष देवता थे ही। डॉ. शर्मा का निष्कर्ष है कि भारतीय देव प्रतीक ही दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचा है।

भारत का लोक जीवन शिव अभीप्सु है। शिव और लोकमंगल पर्यायवाची हैं। हिन्दू अनुभूति में ब्रह्म, विष्णु और महेश की त्रयी है। लेकिन ब्रह्म और विष्णु भी शिव उपासक थे। वायु पुराण 55वें अध्याय के अनुसार राजा बलि को जीतने के बाद विष्णु ने देवों से कहा, जो स्रष्टा है, काल के भी काल हैं जिसने ब्रह्म के साथ मिलकर संसार रचा है, उन्हीं के प्रसाद से यह विजय मिली है। विष्णु ने एक वृत्तांत सुनाया, पहले सब तरफ महा अंधकार था। सब कुछ विष्णु में समाहित था। दूर एक दिव्य पुरुष सहस्रों सूर्यों की आभा से चमक रहे थे। वे ब्रह्म जी थे। दोनों में वार्त्ता चली कि उत्तर दिशा में एक महाज्योति उगी। ब्रह्म उस ज्योति का छोर देखने ऊपर और विष्णु नीचे चले। वे एक हजार वर्ष तक चले किन्तु अन्त नहीं मिला। न ब्रह्मा को न विष्णु को। उन्होनें आराधना की, शिव प्रकट हुए। महाभारत के कर्ण पर्व में एक मजेदार कथा है। तारकासुर के पुत्रों ने तपस्या करके ब्रह्म से अति सुरक्षित देवो दानवों से अबध्य नगराकार विमान पाया। इन्द्र भी उस पुर को नहीं वेध सके। श्रीकृष्ण ने इन्द्र को बताया महादेव ही इन पुरों को वेध सकते हैं। ब्रह्मा सहित सभी देव शिव के पास पहुचें। शिव ने असुरों को मारने का वचन दिया पर शस्त्र देवों से मांगे। विष्णु, चन्द्रमा और अग्नि को वाण बनाया, पृथ्वी रथ बनी, मन्दराचल धुरी बना। आदि। ऋग्वेद आदि वेद व पुराण आगे–आगे चलने वाले सैनिक बने। अथर्वा अंगिरा पहियों के रक्षक बने। शिव ने असुरों का पुर मार गिराया।

महाभारत की इस कथा में आधुनिक समाज के लिए खूबसूरत प्रबोधन है। शिव महाकाल हैं वे किसी को भी मार सकते थे। फिर ब्रह्म इन्द्र आदि शक्तिशाली देवता भी हैं लेकिन शिव सबको साथ लेकर चलते हैं वे प्रकृति की तमाम शक्तियों, पृथ्वी आदि को उपकरण बनाते हैं। रथ के आगे–आगे वेदों का चलना ध्यान देने योग्य है। राष्ट्र जीवन के संचालन में आदर्श और सिध्दांत की महत्ता है। वेद यहां आदर्श का प्रतीक हैं। अथर्वा अंगिरा द्वारा शिव के रथ चक्र की देखभाल करने का मूल अर्थ है कि हम आचार्यो के मार्गदर्शन में ही अपना जीवन चक्र चलाए।

वेद, पुराण और महाभारत कपोल कल्पित कविता नहीं हैं। इनमें इतिहास और विज्ञान के तथ्य हैं। उपनिषद् दर्शन ग्रन्थ है। रुद्र शिव श्वेताश्वतर उपनिषद् में भी हैं – एको रुद्र द्वितीयो नास्ति। यजुर्वेद का 16वां अध्याय रूद्र उपासना पर है। ऋषि, रुद्र का निवास पर्वत की गुहा मे बताते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। चौथे मंत्र में वे रुद्र 'शिवेन वचसा' है, शिव हैं। पांचवें में वे प्रमुख प्रवक्ता, प्रथम पूज्य हैं। वे नीलकण्ठ 'नमस्ते अस्तु नीलग्रीवाय' हैं। (मंत्र 8) फिर वे सभारूप हैं, सभापति भी हैं। (मंत्र 24) सेना और सेनापति भी (मंत्र 25) वे सृष्टि रचना के आदि मे प्रथम पूर्वज हैं और वर्तमान में भी विद्यमान हैं। वे ग्राम गली में विद्यमान हैं, राजमार्ग में भी। वे पोखर, कूप और नदी मे भी उपस्थित हैं। वायु प्रवाह, प्रलय, वास्तु, सूर्य, चन्द्र मे भी वे उपस्थित हैं। (मंत्र 37–39) मंत्र 49 में वे रुद्र फिर शिव 'या ते रुद्रशिवा' हैं। मंत्र 51 में वे इष्टफल दायक 'शिवतम शिवोः' हैं। वे ऋग्वेद में हैं, वे यजुर्वेद में हैं। एक जैसे हैं। रूद्र शिव हैं, शिव रूद्र हैं। रामायण और महाभारत काल में है। उनके नाम पर 'शिव पुराण' अलग से उपलब्ध है। रुद्र शिव ऋग्वैदिक काल की और भारत की ही देव प्रतीति हैं। वे सम्पूर्ण अस्तित्व की विराट ऊर्जा का प्रतीक हैं। ठीक वैसे ही जैसे अदिति, अज, पुरुष आदि वैदिक देव प्रतीक हैं। पुराण कथाओं और भारत के लोकजीवन में वे शिव, रुद्र भोले शंकर भी हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की देवत्रयी में एक विशिष्ट देव हैं। ❑❑

प्रधानमंत्री मोदी ने दी सबसे पहले जीत की बधाई

बांग्लादेश में रहमान युग

बांग्लादेश में जातीय संसद के लिए 12 फ़रवरी 2026 को संपन्न राष्ट्रीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की दो तिहाई बहुमत से विजय और और उसके अध्यक्ष तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की संभावना ने भारत और बांग्लादेश के सम्बन्धों में सकारात्मक परिवर्तन के संकेत दिये हैं। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध के कारण बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दो तिहाई बहुमत की धरातल पर सत्यता संदिग्ध है। भविष्य में भारत और बांग्लादेश के आपसी सम्बन्धों में किस प्रकार सुधार आ सकता है, इसके लिए भारत को बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक स्थिति और नयी सरकार की चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के समन्वय पर दृष्टि रखनी आवश्यक है।

देश भर में कट्टरपंथियों द्वारा प्रदर्शनों के बाद अवामी लीग पार्टी की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पदच्युत करने और उनको देश से पलायन को विवश करने के पश्चात मोहम्मद युनूस के 8 अगस्त 2024 को अभीक्षक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। मोहम्मद युनूस के छोटे से कार्यकाल में बांग्लादेश की राजनीति में जितने नकारात्मक प्रभाव हुए उसने न केवल उस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया बल्कि भारत के साथ उनका शत्रुतापूर्ण व्यवहर और पाकिस्तान, चीन एवं अमेरिका के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध गतिविधियों का चक्रव्युह खड़ा किया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या, उनके घरों और मंदिरों में आगजनी, लूटपाट मोहम्मद युनूस सरकार के परोक्ष और अपरोक्ष समर्थन से होती रहीं। अवामी लीग पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएँ भी होती रहीं। पड़ोसी देशों को प्रथम प्राथमिकता देने की विदेश नीति के अनुपालन करने के कारण भारत की ओर से अत्यधिक संयम रखने के बावजूद मोहम्मद युनूस भारत विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहे और पाकिस्तान के कट्टरपंथी तत्वों के साथ मिलकर भारत की संप्रभुता को भी आहत करने के निष्फल प्रयास करते रहे। भारत की ओर से बांग्लादेश को पारगमन की सुविधाएं रोकने और गंगा नदी बँटवारे के समझौते के पुनरावलोकन करने के प्रयास भी हुए।

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और बांग्लादेश के मीडिया और समाचार पत्रों में बांग्लादेश और

बांग्लादेश में चाहे जो सरकार हो, जैसी भी राजनीतिक परिस्थितियाँ हों, आधा बांग्लादेश भारत में घुसपैठियों के रूप में रहता हैं और पूरे देश में इन घुसपैठियों के विरुद्ध रोष हैं।

– विनोद जौहरी

भारत के सम्बन्धों का आंकलन भारत के लिए विश्वसनीय आधार नहीं हो सकता और बांग्लादेश के भविष्य का आंकलन करना भी जल्दबाज़ी होगी। मोहम्मद युनूस और तारिक रहमान दोनों बांग्लादेश की मुख्यधारा के राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं और निश्चित रूप से विदेशी हस्तक्षेप की दृष्टि से संवेदनशील हैं। क्योंकि मोहम्मद युनूस राष्ट्रीय चुनावों में भागीदार नहीं थे इसलिए अब उस देश की राजनीति और प्रशासन में उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु जिस प्रकार उन्होने भारत और बांग्लादेश के सम्बन्धों पर कुठराघात किया, विदेशी ताकतों द्वारा उनको दिये गए निर्देशों का पालन उन्होने समयबद्ध सीमा में कर दिया और उनके रोल का पटाक्षेप हो गया। इसकी भरपाई करना बांग्लादेश की नयी सरकार का ही कर्तव्य है।

मोहम्मद युनूस के लगभग अट्ठारह महीनों के कार्यकाल में यह सिद्ध हो गया कि इस्लामिक देशों ने बांग्लादेश की उपद्रवी स्थिति में न कोई रुचि दिखाई और न अपना हाथ बढ़ाया। न किसी इस्लामिक देश ने पदच्युत और अपने प्राण बचाने को विवश शेख हसीना को शरण दी और न ही बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनावों में अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध हटाने को लेकर कोई प्रतिक्रिया दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अपने हितों को साधता है और उसमें निहितार्थ ताक़तें भी बांग्लादेश की हितैषी नहीं हैं। जो बांग्लादेश की सेना राष्ट्रीय चुनावों में निष्पक्षता का दावा कर रही थी वही सेना और पुलिस मोहम्मद युनूस के कार्यकाल में हिंदुओं पर अत्याचार, हिन्दू मंदिरों और घरों में आगजनी और लूटपाट में मूदर्शक थी। इतिहास साक्षी है कि इस्लामिक देशों में लोकतन्त्र का कोई महत्व नहीं है और चुनावों में विरोधी दलों पर प्रतिबंध के कारण पारदर्शिता नहीं होती इसलिए शासन, प्रशासन, विदेश और रक्षा नीति, अर्थव्यवस्था,

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और बांग्लादेश के मीडिया और समाचार पत्रों में बांग्लादेश और भारत के संबंधों का आंकलन भारत के लिए विश्वसनीय आधार नहीं हो सकता और बांग्लादेश के भविष्य का आंकलन करना भी जल्दबाज़ी होगी।

अल्पसंख्यकों के साथ दमन कट्टरपंथियों के नियंत्रण में रहता है। आर्थिक रूप से अशक्त होने के कारण इस्लामिक देशों की निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, चीन, अमेरिका और पश्चिमी देशों पर रहती है इसलिए विदेशी ताक़तें वहाँ प्रभावी रहती हैं। बांग्लादेश की यह परिस्थितियाँ निश्चित रूप से भारत सरकार की दृष्टि में होंगी। यही परिद्रश्य सम्पूर्ण मध्यपूर्व एशिया में आच्छादित हैं। क्योंकि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अब महाशक्ति के रूप में भारत उभर रहा है, तो उसको रोकने के लिए विश्व की महाशक्तियों को इस्लामिक देश पाकिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश ही अनुकूल दिखाई देते हैं और वही उनकी शतरंज की बिसात हैं। ऐसे वैश्विक परिद्रश्य में भारत को अपनी पड़ोसी देशों को प्रथम प्राथमिकता देने की विदेश नीति को पाकिस्तान और बांग्लादेश के परिपेक्ष्य में बदलने पर विचार करने की आवश्यकता है। पड़ोसी देशों को प्रथम प्राथमिकता देने की विदेश नीति श्रीलंका, नेपाल और भूटान के लिए ही सम्यक है।

बांग्लादेश में चाहे जो सरकार हो, जैसी भी राजनीतिक परिस्थितियाँ हों, आधा बांग्लादेश भारत में घुसपैठियों के रूप में रहता हैं और पूरे देश में इन घुसपैठियों के विरुद्ध रोष हैं। वर्तमान में मतदाता गहन परीक्षण में इन घुसपैठियों को हटाने की कार्यवाही प्रगति में है। कानून के अनुसार इन पर भारत छोडने का भी दवाब है। इन घुसपैठियों की बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार की सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी उपस्थिति और जन सख्या परिवर्तन देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं और इनका अपराध तंत्र, नशीले पदार्थो का व्यापार, देश विरोधी गतिविधियों का जाल पूरे देश में प्रशासन के लिए चिंताजनक है। इनको देश की मतदाता सूचियों से हटाना ही पर्याप्त नहीं बल्कि देश से निकालना अपरिहार्य है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की कार्यवाही शीघ्र करने की आवश्यकता है।

पिछले दिनों वक़्त संशोधन के विरोध में बिहार के सीमांचल से सटे मुर्शिदाबाद में अचानक भारी हिंसा, हत्या, आगजनी और उपद्रवों ने यह संकेत दिए हैं कि बांग्लादेश से सटे क्षेत्रों में जहाँ भारी जनसंख्या परिवर्तन, घुसपैठियों के जमाव और धर्मांतरण के फलस्वरूप मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विभाजनकारी गतिविधियों की आशंका है। ऐसी परिस्थितियों में बांग्लादेश की नई सरकार से सम्बन्धों को सामान्य करना एक बड़ी चुनौती है।

बांग्लादेश के साथ गंगा नदी का बंटवारा भारत के हितों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण है क्योंकि इस बँटवारे के कारण फरक्का बांध को पूरा जल नहीं मिलता और हूगली नदी में जल कम रहता हैं जिससे बंगाल के किसानों का अहित होता है। भारत के हितों की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश के साथ 2026 में समाप्त हो रही गंगा जल संधि पर पुनर्विचार आवश्यक है।

जो देश भारत की सीमा से 95 प्रतिशत बंधा है और जिसका अस्तित्व ही भारत पर निर्भर है उसको भी अपनी राजनीतिक व्यवस्था में भारत को वरीयता देनी चाहिए। वह चाहे कितनी भी विदेशी शक्तियों पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करे, उसके लिए भारत से बैर रखना उचित नहीं है। ❑❑

डिजिटल लत के साये में बचपन, टूटती जिंदगियां और अधूरी सोशल मीडिया सुरक्षा नीति

भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां बच्चों की दुनिया तेजी से बदल रही है. खिलौनों, मैदानों और दोस्तों की जगह मोबाइल स्क्रीन ने ले ली है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे–धीरे हमारी आंखों के सामने पनपा। गाजियाबाद की तीन नाबालिग बहनों और भोपाल के एक 14 साल के बच्चे की मौत ने इस सच्चाई को बेरहमी से उजागर कर दिया है कि डिजिटल दुनिया अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रही, बल्कि कई मासूम जिंदगियों के लिए मानसिक जाल बन चुकी है। ये घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं हैं, बल्कि उस सिस्टम का नतीजा हैं जहां बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा अहमियत डिजिटल मुनाफे को दी जा रही है। भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच ने पिछले एक दशक में क्रांति ला दी।

सरकारी और निजी रिपोर्टों के मुताबिक आज देश में 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं और इनमें करीब एक तिहाई बच्चे और किशोर हैं। एक औसत भारतीय बच्चा रोजाना 3 से 6 घंटे स्क्रीन पर बिता रहा है। कोरोना महामारी के दौरान यह समय और बढ़ा। ऑनलाइन पढ़ाई ने मोबाइल को बच्चों की जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बना दिया. लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद वही मोबाइल गेमिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैलेंज का प्रवेश द्वार बन गया। धीरे–धीरे बच्चों के लिए असली दुनिया उबाऊ और स्क्रीन के भीतर की दुनिया ज्यादा आकर्षक लगने लगी।

ऑनलाइन गेमिंग का मनोविज्ञान बेहद जटिल है। कई गेम्स और टास्क–बेस्ड ऑनलाइन ट्रेंड इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि यूजर को लगातार अगला स्तर पूरा करने की बेचैनी बनी रहे। हर टास्क पूरा होने पर दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो खुशी और संतुष्टि का एहसास देता है। यही प्रक्रिया बार–बार दोहराई जाती है और लत बन जाती है। बच्चों का दिमाग, जो अभी विकास की अवस्था में होता है, इस प्रभाव को समझ नहीं पाता। वे यह फर्क नहीं कर पाते कि गेम का दबाव और असली जिंदगी की अहमियत क्या है। गाजियाबाद की तीनों बहनों के मामले में भी शुरुआती जांच यही संकेत देती है कि वे एक टास्क–बेस्ड ऑनलाइन गेम से भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी थीं, जहां गेम पूरा करना ही उनका लक्ष्य बन गया था।

बच्चों का भविष्य डिजिटल बाजार के हवाले करना सबसे बड़ा जोखिम है, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

–अजय कुमार

समस्या सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं. रील्स, शॉर्ट वीडियो और लाइक–शेयर का सिस्टम बच्चों को लंबे समय तक स्क्रीन से बांधे रखता है। कंपनियों का मुनाफा यूजर के समय पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा समय बच्चा स्क्रीन पर रहेगा, उतना ज्यादा डेटा, उतना ज्यादा विज्ञापन और उतनी ज्यादा कमाई। लेकिन इस दौड़ में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की कीमत कोई नहीं गिनता। भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए बच्चों की सुरक्षा को लेकर नियम तो हैं, लेकिन वे या तो अधूरे हैं या सख्ती से लागू नहीं होते।

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि डिजिटल एडिक्शन बच्चों में अकेलापन, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और अवसाद को बढ़ाता है। कई अध्ययनों में यह सामने आया है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों के व्यवहार में आक्रामकता और सामाजिक दूरी पैदा

करता है। बच्चे परिवार से कटने लगते हैं और ऑनलाइन दुनिया में मिले अनजान लोगों या कैरेक्टर्स से ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। यही स्थिति उन्हें आसानी से मैनिपुलेट होने के खतरे में डाल देती है। ब्लू व्हेल, मोमो चैलेंज या अन्य टास्क–बेस्ड ट्रेंड इसी मानसिक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। दुनिया के कई देशों ने इस खतरे को गंभीरता से लिया है। चीन ने बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त समय सीमा तय की है। वहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे तय घंटों से ज्यादा गेम नहीं खेल सकते। दक्षिण कोरिया ने भी रात के समय बच्चों के गेमिंग पर रोक जैसे नियम लागू किए। यूरोप के कई देशों में सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों के डेटा और मानसिक सुरक्षा के लिए जवाबदेह ठहराया गया है। वहां उम्र सत्यापन, कंटेंट फिल्टर और पैरेंटल कंट्रोल को अनिवार्य बनाया गया है। इसके उलट भारत में ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस और स्पष्ट नीति अब भी अधूरी है।

माता–पिता की भूमिका भी इस संकट में अहम है, लेकिन उन्हें पूरी तरह दोषी ठहराना सही नहीं होगा। बदलती तकनीक की रफ्तार के साथ पैरेंट्स खुद जूझ रहे हैं। कई बार वे बच्चों की ऑनलाइन भाषा, गेम्स या प्लेटफॉर्म्स को समझ ही नहीं पाते. जब समस्या नजर आती है, तब तक हालात बिगड़ चुके होते हैं। डांट, मोबाइल छीनना या सख्ती अक्सर बच्चों को और ज्यादा दूर धकेल देती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि संवाद, भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि वे अपनी उलझनें परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। यह सवाल अब टालने लायक नहीं रहा कि क्या भारत को भी बच्चों के लिए सख्त सोशल मीडिया और गेमिंग नीति की जरूरत है। क्या उम्र सत्यापन को मजबूत नहीं किया जाना चाहिए. क्या कंपनियों को यह जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि उनके प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित हों। जब दूसरे देश यह कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं। डिजिटल दुनिया से बच्चों को पूरी तरह दूर करना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें बिना सुरक्षा के छोड़ देना भी एक तरह की लापरवाही है।

गाजियाबाद और भोपाल की घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि तकनीक जितनी ताकतवर है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है, अगर उसका इस्तेमाल बिना संतुलन के हो। यह सिर्फ एक परिवार या एक शहर की कहानी नहीं है। यह पूरे समाज के लिए चेतावनी है। अगर अब भी नीति, समाज और परिवार एक साथ नहीं आए, तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। तब हमारे पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बच्चों का भविष्य डिजिटल बाजार के हवाले करना सबसे बड़ा जोखिम है, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।❑❑

अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ (उ. प्र.)।

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http://swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC: BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

मुक्त व्यापार समझौते में भारत वसुधैव कुटुम्बकम के भाव

दिनांक 27 जनवरी 2026 को यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों के साथ भारत ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। अब, इस समझौते की शर्तों को इन देशों की संसद द्वारा पारित किया जाएगा, इसके बाद यह मुक्त व्यापार समझौता यूरोपीय यूनियन एवं भारत के बीच होने वाले विदेशी व्यापार पर लागू हो जाएगा। इस मुक्त व्यापार समझौते को "मदर आफ ऑल डील्स" कहा जा रहा है, क्योंकि, यह मुक्त व्यापार समझौता विश्व के 28 देशों के उस भूभाग पर लागू होने जा रहा है, जहां विश्व की 30 प्रतिशत आबादी निवास करती है। पृथ्वी के इस भूभाग पर 200 करोड़ से अधिक नागरिकों का निवास है। इन 28 देशों की संयुक्त रूप से विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी (संयुक्त रूप से) अर्थव्यवस्था (यूरोपीय यूनियन – 22 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर) एवं चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (भारत – 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर) के बीच यह मुक्त व्यापार समझौता सम्पन्न होने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर होने वाले विदेशी व्यापार में इन समस्त देशों की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत है। पूरी दुनिया में 33 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी व्यापार होता है, इसमें से 11 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी व्यापार उक्त 28 देशों द्वारा किया जाता है।

उक्त वर्णित मुक्त व्यापार समझौता विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। इसके पूर्व, सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के रूप में चीन एवं 10 आशियान देशों के बीच सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते को माना जाता है। यह केवल एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन के 27 देशों एवं भारत के बीच साझा समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है। इस समझौते में पूरी दुनिया की आर्थिक दशा एवं दिशा बदलने की क्षमता है। उक्त व्यापार समझौता को

यूरोपीय यूनियन के समस्त 27 देशों के साथ सम्पन्न किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते से भारत के लिए अतिलाभप्रद स्थिति बनने जा रही है।
– स्वदेशी संवाद

सम्पन्न करने के प्रयास पिछले 18 वर्षों से हो रहे थे। परंतु, कुछ विपरीत परिस्थितियों के चलते इस समझौते को सम्पन्न होने में इतना लम्बा समय लग गया है, अतः यह अब भारत एवं यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। उक्त मुक्त व्यापार समझौते के सम्पन्न होने के पश्चात वर्ष 2032 तक यूरोपीयन यूनियन के सदस्य देशों एवं भारत के बीच विदेशी व्यापार के दुगना होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इसके पूर्व भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच भी मुक्त व्यापार समझौता सम्पन्न किया जा चुका है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री भी संभवतः मार्च माह में भारत के दौरे पर आने वाले है और भारत एवं कनाडा के बीच भी कुछ क्षेत्रों में व्यापार समझौता सम्पन्न होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। अमेरिका मुक्त व्यापार समझौतों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है ताकि भारत एवं अन्य समस्त देशों में निवासरत नागरिकों को इन समझौतों से लाभ मिले। यह भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुम्बकम के भाव को दर्शाता है। भारत की इस नीति के चलते ही विश्व के कई देश अब भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते शीघ्र ही सम्पन्न करना चाह रहे हैं। हाल के समय में वैश्विक स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में भारी उथल–पुथल दिखाई दे रही है। भारत एवं यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों के बीच सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते से इस उथल पुथल में कुछ सुधार आता हुआ दिखाई देगा।

भारत में कृषि एवं डेयरी क्षेत्र अतिसंवेदनशील है। क्योंकि, भारत की कुल आबादी का लगभग 60 प्रतिशत भाग आज भी ग्रामीण इलाकों में उक्त क्षेत्रों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। अतः उक्त दोनों क्षेत्रों को मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा गया है। हां, भारत के समुद्री उत्पाद उद्योग, वस्त्र एवं परिधान उद्योग, जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग, चमड़ा उद्योग, खिलौना उद्योग जो श्रम आधारित उद्योग हैं, को उक्त मुक्त व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ होगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन के समस्त 27 देशों द्वारा भारत से उक्त उत्पादों के आयात पर आयात ड्यूटी को शून्य किया जा रहा है। वर्तमान में भारत से समुद्रीय उत्पादों के निर्यात पर 26 प्रतिशत का आयात कर लगाया जाता है, जिसे मुक्त व्यापार समझौता के लागू होने के पश्चात शून्य कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, वस्त्र एवं परिधान के आयात पर वर्तमान में लागू 12 प्रतिशत के आयात कर को शून्य किया जा रहा है, खिलौना पर लागू 4.7 प्रतिशत के आयात कर को शून्य, जेम्स एवं ज्वेलरी के आयात पर 4 प्रतिशत से शून्य, केमिकल उत्पादों के आयात पर 12.8 प्रतिशत से शून्य, चमड़ा से निर्मित उत्पादों के आयात पर 17 प्रतिशत से शून्य, फर्नीचर उत्पादों के आयात पर 10.7 प्रतिशत से शून्य आयत कर किया जा रहा है।

यूरोपीय यूनियन के 27 देश, जो विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हैं, में जन्म दर पिछले कई वर्षों से लगातार गिर रही है एवं कुछ देशों में तो यह शून्य के स्तर पर पहुंच गई है जिससे इन देशों में प्रौढ़ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिकों का इन देशों में नितांत अभाव दिखाई देता है। अतः इन देशों में श्रमबल की भारी कमी है। उक्त मुक्त व्यापार समझौते के सम्पन्न होने के पश्चात भारतीय नागरिकों को यूरोपीय यूनियन के समस्त 27 देशों में तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, आदि में रोजगार के भारी मात्रा में अवसर प्राप्त होंगे। इन समस्त देशों द्वारा भारतीय नागरिकों को वीजा प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। युनाईटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रान्स आदि जैसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे देशों में भारतीय इंजिनीयरों एवं डाक्टरों की भारी मांग है। उक्त देशों द्वारा भारतीयों के परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने के अवसर भी प्रदान करने सम्बंधी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। भारतीय विद्यार्थियों द्वारा यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरांत 9 माह से 12 माह तक का समय रोजगार तलाशने के लिए प्रदान किया जाएगा। इस समयावधि तक भारतीय युवाओं को इन देशों में प्रवास की अनुमति प्रदान की जाएगी।

भारतीय कारीगरों के लिए अब वैश्विक बाजार खुल रहा है। साथ ही, भारत अब विनिर्माण इकाईयों का वैश्विक केंद्र बन सकता है। क्योंकि, यूरोपीयन यूनियन के समस्त देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हैं एवं वे अपनी सम्पत्ति/पूंजी का निवेश भारत में विनिर्माण इकाईयों में कर सकते हैं एवं कुछ लाभप्रद क्षेत्रों में वे अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना भी कर सकते हैं। अधिक उत्पादन इकाईयों की स्थापना से भारत में रोजगार के अधिक अवसर भी निर्मित होंगे। इससे भारत में बेरोजगारी की समस्या का हल भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।

भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को इस दृष्टि के साथ सम्पन्न किया जा रहा है ताकि इससे भारत के किसान, मजदूर, कारीगर, पेशेवर नागरिकों एवं सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्योगों को विशेष लाभ हो। यूरोपीयन यूनियन के समस्त 27 देशों में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र का आकार 26,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है, इससे भारत से वस्त्र एवं परिधान का निर्यात वर्तमान में 64,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इसी प्रकार, चमड़ा

उत्पादों का बाजार 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है एवं जेम्स एवं ज्वेलरी का बाजार 7,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। 27 देशों में इस विशाल क्षेत्र में भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग एवं अन्य उत्पादों को प्रवेश मिलने से भारत में श्रम आधारित कई सूक्ष्म, छोटी एवं मध्यम इकाईयों को लाभ होने जा रहा है। लगभग इसी प्रकार का लाभ अन्य क्षेत्रों यथा, समुद्री उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, खिलोना उत्पाद, जेम्स एवं ज्वेलरी उत्पाद, केमिकल उत्पाद, फर्नीचर उत्पाद आदि, में कार्यरत इकाईयों की भी होने जा रहा है। इन क्षेत्रों में कार्यरत विनिर्माण इकाईयों के व्यापार में वृद्धि का आश्य सीधे–सीधे अधिक श्रमबल की आवश्यकता होना भी है, जिसकी पूर्ति आज विश्व में केवल भारत ही कर सकता है।

रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। इस क्षेत्र में भारत का अंतिम लक्ष्य आत्मनिर्भरता हासिल करने का है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन द्वारा यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों को सुरक्षा के सम्बंध में अमेरिका पर निर्भर नहीं रहते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह दी है। अतः यूरोपीय देश अपने सुरक्षा बजट में अत्यधिक वृद्धि करने का विचार कर रहे हैं। भारत के लिए ऐसे समय पर उक्त मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाना एक सुनहरे अवसर के रूप में सामने आया है। इससे सुरक्षा के क्षेत्र में उत्पादन कर रही भारतीय कम्पनियों को यूरोपीय यूनियन का अति विशाल बाजार मिलने जा रहा है। इसी के साथ ही यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों से सुरक्षा के क्षेत्र में उच्च तकनीकी का हस्तांतरण भारतीय कम्पनियों को सम्भव हो सकेगा। कुल मिलाकर यूरोपीय यूनियन के समस्त 27 देशों के साथ सम्पन्न किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते से भारत के लिए अतिलाभप्रद स्थिति बनने जा रही है। ❑❑

कौशल विकास से जुड़े ग्रामीण शिक्षा

भारत को वैज्ञानिकों, डाक्टरों और इंजीनियरों को देश माना जाता है और विश्व में इनका डंका बजता है। लेकिन जब ग्रामीण शिक्षा की बात आती है तो हमारी गिनती नीचे फिसल जाती है। इन दिनों देश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड़ परीक्षा चल रही है। केवल सीबीएसई के मार्फत लगभग 46 लाख विद्यार्थी, जिसमें 27 लाख हाई स्कूल तथा लगभग 19 लाख इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त देश में कुल 66 परीक्षा बोर्ड है जिसके जरिये बड़ी तादाद में विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने वालों में शहरी और ग्रामीण हिस्सेदारी 40 और 60 की है। अमूमन शहरी विद्यार्थी उच्च शिक्षा की तैयारी पहले से ही करने लगते है लेकिन ग्रामीण पृष्टभूमि के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा आसान नहीं है। संसाधनों के अभाव के कारण अभिभावकों में भी असमंजस की स्थिति रहती है और वे चाहकर भी कई बार अपने मेधावी बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाने में असफल रह जाते हैं।

ग्रामीण छात्रों के सामने कई तरह की चुनौतियाँ हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच, पुराना पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा कुछ ऐसी बाधाएँ हैं। इन चुनौतियों के कारण ग्रामीण छात्रों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, खासकर आज की दुनिया में जहाँ सफलता के लिए न केवल अकादमिक ज्ञान बल्कि विविध कौशलों की भी आवश्यकता होती है।

"21वीं सदी के कौशल" शब्द उन व्यापक क्षमताओं को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों को आधुनिक व्यक्तिगत, शैक्षणिक और व्यावसायिक परिवेश में सफल होने में मदद करती हैं। इनमें – आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान, सहयोग और टीम वर्क, डिजिटल साक्षरता, संचार कौशल के साथ–साथ अकादमिक क्षेत्र से परे के कौशल, वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईक्यू), सतत विकास और पर्यावरण जागरूकता आदि आवश्यक है।

कुल मिलाकर कौशल विकास न केवल आजीविका का साधन है, बल्कि सामान्य दिनचर्या में स्वयं के जीवंत और ऊर्जावान बनने का माध्यम भी है। ग्रामीण युवा, जो रील के चक्कर में पड़कर अपनी रियल जिंदगी नष्ट कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा को उर्ध्वगामी बनाया जाए, उनमें तकनीक क्षमता विकसित की जाए, रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे की विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सके। वोकेशनल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को अनुकूल माहौल प्रदान करते हुए कौशल विकास द्वारा राष्ट्र की प्रगति में जवाबदेही के साथ जोड़ा जाए। स्कूली स्तर पर प्रतिष्ठा के साथ आधुनिक कृषि तकनीक, जैविक खेती, बागवानी, नर्सरी प्रबंधन, हस्तशिल्प, सिलाई–कढ़ाई, डिजिटल साक्षरता, इलैक्ट्रीशियन, पलेंबिंग, आयुर्वेद उत्पादन निर्माण, आदि पर फोकस करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और छात्रों में शिक्षा के प्रति रूझान भी बढ़ेगा।

(स्वदेशी संवाद)

योगी सरकार ने सिंगापुर में किये 6650 करोड़ के समझौते

उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति को विस्तार देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चार दिवसीय विदेश यात्रा से बड़े निवेश की राह खुली है, वहीं राजनयिक रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। इस दौरान सिंगापुर में मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ गहन चर्चा की और जी–टू–बी बैठकों का आयोजन भी किया गया, जिसमें 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, जहां सीएम ने उत्तर प्रदेश की स्थिर नीतियों, मजबूत कानून व्यवस्था और बेहतर बुनियादी ढांचे की ताकत बताई। पहले ही दिन तीन महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनकी राशि छह हजार छह सौ पचास करोड़ रुपये बताई जा रही है। इन समझौतों से शहरी विकास, स्मार्ट शहर परियोजनाएं, जल प्रबंधन और कौशल विकास के क्षेत्रों में प्रगति होगी। सिंगापुर के गृह मंत्री और विदेश मंत्री से उनकी भेंट ने राजनयिक स्तर पर भी मजबूती प्रदान की। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित कर प्रदेश के अवसरों से अवगत कराया और निवेश का भरोसा जगाया।

इस दौरे का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को निर्माण केंद्र और एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाना था। योगी ने निवेशकों को बताया कि प्रदेश में एकल खिड़की प्रणाली से अनुमोदन प्रक्रिया सरल हो गई है, बिजली–पानी की आपूर्ति निर्बाध है और एक्सप्रेसवे तथा औद्योगिक पार्कों का जाल बिछ चुका है। सिंगापुर जैसे विकसित देश ने हमेशा प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्रों में नेतृत्व किया है, इसलिए वहां से प्राप्त सहयोग प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा। रोड शो के माध्यम से उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित किया और प्रदेश की 36 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का वादा किया। पिछले वैश्विक निवेशक समिट में 35 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले थे, जिन पर कार्य शुरू हो चुका है, और यह दौरा उसी श्रृंखला का हिस्सा था। सिंगापुर से लौटते हुए योगी ने कहा कि यह यात्रा निवेश की नई लहर लाएगी, जो लाखों नौकरियां पैदा करेगी।

जापान प्रवास के दौरान योगी आदित्यनाथ ने यमनाशानी प्रांत के राज्यपाल से भेंट की और उच्च गति रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। जापान की उन्नत रेल प्रौद्योगिकी उत्तर प्रदेश के लिए वरदान साबित हो सकती है, खासकर मगलेव ट्रेन

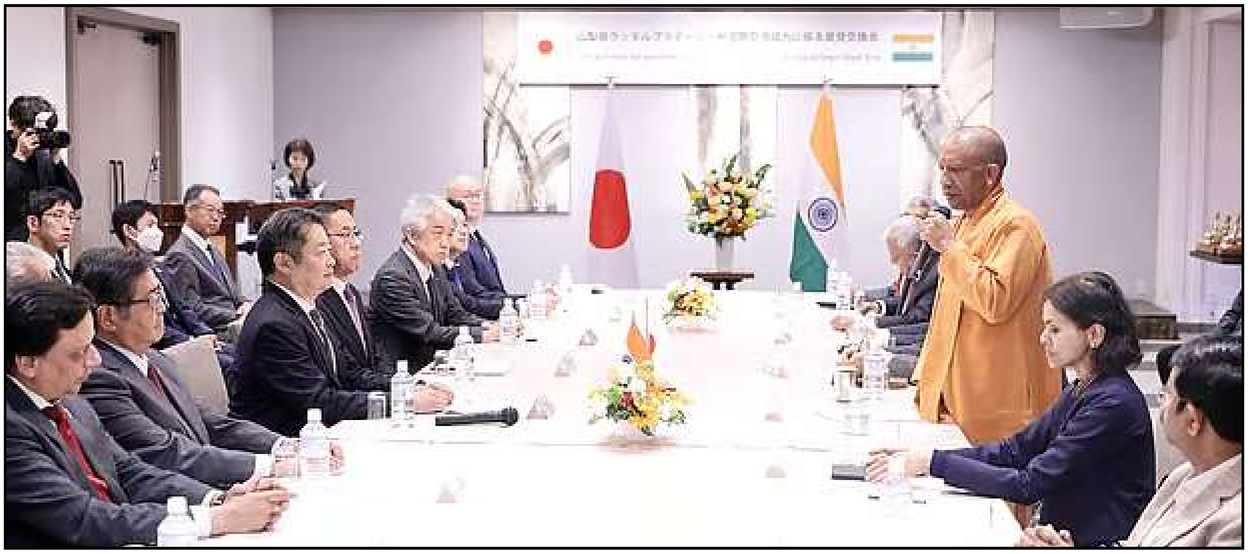

जैसी परियोजनाओं के लिए। उन्होंने वहां भारतीय समुदाय के साथ सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया और निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला। जापान के निवेशक निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में रुचि दिखा रहे हैं। योगी ने जापानी कंपनियों को प्रदेश के विशाल बाजार और कुशल श्रमिकों के बारे में बताया। इस दौरे से प्राप्त प्रतिबद्धताएं ऊर्जा, परिवहन और तकनीकी क्षेत्रों को मजबूत करेंगी। जापान जैसे देश से निवेश आने से प्रदेश का निर्यात बढ़ेगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उत्तर प्रदेश की स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर, चार दिनों में हुई बैठकों ने दर्जनों संभावनाएं खोली हैं, जो राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होंगी।

इस यात्रा से उत्तर प्रदेश को निवेश के अलावा अन्य लाभ भी मिले। सिंगापुर से प्राप्त समझौते जल प्रबंधन में नई तकनीक लाएंगे, जो गंगा सफाई और नदी जोड़ परियोजनाओं को गति देंगे। कौशल विकास के क्षेत्र में साझेदारी से युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे बेरोजगारी कम होगी। जापान से उच्च गति परिवहन प्रौद्योगिकी हासिल होने से एक्सप्रेसवे और मेट्रो परियोजनाएं तेज होंगी। योगी सरकार ने पहले ही निवेश नीतियों को सरल बनाया है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ। प्रदेश अब निवेशकों का भरोसेमंद गंतव्य बन चुका है, जहां भूमि बैंक, सस्ती बिजली और सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध है। इस दौरे ने वैश्विक ब्रांडों का विश्वास बढ़ाया, जैसा कि वित्तीय वर्ष में सैकड़ों परियोजनाओं से स्पष्ट है। निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगेंगे, जिससे प्रवासन रुकेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

इन निवेशों से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रगति होगी। लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, खासकर लखनऊ, नोएडा और वाराणसी जैसे शहरों में।

योगी आदित्यनाथ की यह यात्रा 2017 के म्यांमार दौरे के बाद पहली थी, जो दर्शाता है कि सरकार विदेशी निवेश पर कितना जोर दे रही है। सिंगापुर और जापान जैसे देशों से निवेश आने से प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा और एक ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य साकार होगा। निवेशकों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा की, जो योगी के शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यात्रा से लौटकर योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और प्राप्त प्रतिबद्धताओं को जमीन पर उतारने के निर्देश दिए। इन निवेशों से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रगति होगी। लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, खासकर लखनऊ, नोएडा और वाराणसी जैसे शहरों में। ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगेंगी, जो किसानों की आय दोगुनी करेंगी। कुल 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ गई यात्रा ने सभी क्षेत्रों को कवर किया।

इस दौरे की सफलता से उत्तर प्रदेश वैश्विक पटल पर चमकेगा। निवेश के अलावा सांस्कृतिक आदान–प्रदान बढ़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जापान के राज्यपाल के साथ चर्चा से सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हो सकते हैं। सिंगापुर की स्मार्ट सिटी तकनीक से प्रदेश के शहर आधुनिक बनेंगे। योगी ने निवेशकों को आश्वासन दिया कि सभी प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही होगी। यह यात्रा न केवल आर्थिक लाभ देगी, बल्कि राज्य की छवि को नया आयाम भी प्रदान करेगी। भविष्य में ऐसे और दौरे होंगे, जो प्रदेश को भारत का इंजन बनाएंगे। निवेश से उद्योग धंधे लगेंगे, बाजार फूलेंगे और कल्याणकारी योजनाएं मजबूत होंगी। योगी आदित्यनाथ का विजन स्पष्ट है– विकसित उत्तर प्रदेश, जो विश्व गुरु भारत का आधार बने। इस दौरे ने सिद्ध कर दिया कि मेहनत और दूर दृष्टि से असंभव कुछ नहीं। प्रदेशवासी गर्व से कह सकते हैं कि उनका राज्य अब वैश्विक निवेश का केंद्र है। ❑❑

(स्वदेशी संवाद)

अखिल भारतीय स्वदेशी संकल्प यात्रा

स्वदेशी जागरण मंच के इतिहास की पहली 'अखिल भारतीय स्वदेशी संकल्प यात्रा' दिनांक 12 जनवरी 2026 को कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर प्रारंभ हुई। यात्रा को तमिलनाडू के नागरकोईल में आयोजित भव्य सभा में अखिल भारतीय सह संगठक श्री सतीश कुमार ने रवाना किया। इस अवसर पर मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर. सुन्दरम की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस यात्रा के पहले यात्री के रूप में नेतृत्व का दायित्व मंच के अखिल भारतीय पर्यावरण प्रमुख श्री दीपक शर्मा को प्रदान किया गया। उनके नेतृत्व में यह यात्रा केरल में 1000 किमी. व तमिलनाडू व पांडेचेरी में 2000 किमी. तक चली। 14 दिनों तक दक्षिण क्षेत्र में चली इस यात्रा में 56 स्थानों पर भव्य एवं यशस्वी कार्यक्रम संपन्न हुए। उल्लेखनीय कार्यक्रम शिवकाशी में 450 प्रमुख व्यापारियों के द्वारा यात्रा का स्वागत एवं भव्य सभा, त्रिची में 1000 नागरिकों के द्वारा स्वागत और सभा, जिसमें स्थानीय लोकसभा सांसद एवं प्रख्यात नेता वाईको के सुपुत्र के अलावा पंजावर मठ के पूज्य स्वामी जी भी उपस्थित रहे। यात्रा का आयोजन एक ऐसे आईटी स्टार्ट–अप ने किया, जिनके उपकरण चंद्रयान में काम कर रहे हैं।

केरल के मल्लपुरम में व्यापारी सभा व त्रिवेन्द्रम में प्रबुद्धजन सभा एवं त्रिशूर की जनसभा उल्लेखनीय रही। इस यात्रा में केरल के तिरूनागपल्लम में मोटरसाईकिलों से 5 किमी. लंबी रेली निकाली गई। यात्रा को केरल के संत अद्वैत आश्रम के संत पूज्य चिदानंद पुरी जी महाराज ने भी सहभागिता की।

इस यात्रा में उद्योगपति, किसान, व्यापारी, उद्यमी, युवा, महिलाएं, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक संस्थान, मेरीटाईम यूनिवर्सिटी, पत्रकार वार्ताएं, सांसद/निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित विभिन्न वर्गों के कार्यक्रम संपन्न हुए। केरल व तमिलनाडू के समाचार पत्रों व टी.वी. चैनलों ने यात्रा को व्यापक कवरेज दिया। तमिलनाडू (उत्तर) के प्रांत संयोजक श्री शेषाद्री सुन्दरम (चेन्नई), प्रांत सह संयोजक सीए शेषाद्रि सुंदरम (सेलम), प्रांत पूर्णकालिक श्री भारत देवेन्द्र, तमिलनाडू (दक्षिण) के प्रांत संयोजक श्री षणमुगम सुंदरम्, पूर्णकालिक श्री उन्नीकृष्णन, तमिलनाडू (उत्तर–दक्षिण) के संगठक श्री सत्यनारायण, केरल प्रांत संयोजक श्री अनिल पिल्लई व पूर्णकालिक श्री पार्थ सरथी तथा श्रीकुमार कवील यात्रा में साथ रहे।

यात्रा का समारोप कार्यक्रम चेन्नै में हुआ। इस अवसर पर तमिलनाडू के महामहिम राज्यपाल श्री टी.एन. रवि, आई. आई.टी. मद्रास के डायरेक्टर पद्मश्री प्रो. वी. कामकोटि, श्री आर. सुन्दरम सहित भारी जनसमूह उपस्थित रहा।

दक्षिण क्षेत्र में अनेक चुनौतियों के बावजूद कार्यकर्ताओं नें यात्रा को सफलता पूर्वक संपन्न करवाया। श्री दीपक शर्मा के नेतृत्व में संपन्न इस यात्रा ने दक्षिण क्षेत्र में स्वदेशी जागरणा मंच के कार्य को सफलतापूर्वक विस्तार दिया।

भारतीय संस्कारों से ही मजबूत होगा परिवारः अन्नदा

स्वदेशी जागरण मंच का भव्य परिवार सम्मेलन निक्को पार्क (जमशेदपुर) में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 500 सदस्य अपने परिवार, बच्चों और महिलाओं के साथ शामिल हुए. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय कुटुंब व्यवस्था को मजबूत करना और पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बीच स्वदेशी जीवनशैली को बढ़ावा देना था। सम्मेलन के अंत में जिला संयोजक राजपति देवी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर जिला प्रचार–प्रसार प्रमुख संगीता श्रीवास्तव, प्रांत युवा प्रमुख पंकज सिंह, स्वावलंबी के निदेशक अशोक गोयल, मुकेश ठाकुर, संजीत सिंह, मनोज सखुजा और रमेश कुमार समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता सपरिवार उपस्थित थे।

सम्मेलन में मुख्य वक्ता और अखिल भारतीय संघर्ष वाहिनी प्रमुख अन्नदाशंकर पाणीग्रही ने कहा कि स्वदेशी आज बिखरा हुआ नहीं, बल्कि संगठित है।

नवाचार, आर्थिक प्रगति की कुंजीः डॉ. धनपत राम अग्रवाल

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (यूआईईटी) में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश की आर्थिक प्रगति में नवाचार, अनुसंधान और पेटेंट की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की दिशा मिली।

मुख्य वक्ता के रूप में इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशन कोलकाता के निदेशक व स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह–संयोजक डॉ. धनपत राम अग्रवाल रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में प्राकृतिक संसाधन, पूंजीगत संसाधन और मानव संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अमेरिका, चीन और भारत की जीडीपी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने बताया कि जिन देशों ने नवाचार, अनुसंधान और पेटेंट पर अधिक ध्यान दिया, वही आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी बने हुए हैं। डॉ. अग्रवाल ने आईपीआर के अंतर्गत नवीनता, आविष्कार और औद्योगिक अनुप्रयोग के महत्व को सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा कि नए अनुसंधान ही नए रोजगार के अवसरों की नींव रखते हैं। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में शोध और नवाचार को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा स्तर से ही नवाचार और अनुसंधान की सोच विकसित करने पर की जोर दिया। साथ ही आईपीआर इकोसिस्टम में रचनात्मकता, उत्पादन, तकनीकी और कानूनी पहलुओं की सही समझ को आवश्यक बताया।

डीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं यूआईईटी के निदेशक प्रो. सुनील ढींगरा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता की अहम भूमिका है और समय के साथ छात्रों की स्टार्टअप के प्रति सोच में सकारात्मक बदलाव आया है।

स्वदेशी मेला के माध्यम से स्व का भाव जगाने का कामः अजय उपाध्याय

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा झारखंड के कई जिलों में स्वदेशी मेला का आयोजन लगातार हो रहा है। बोकारो इस्पात नगर में 25 वर्षों से यह मेला निरंतर लगाया जा रहा है। इस वर्ष यह स्वदेशी मेला मजदूर मैदान सेक्टर 4 में 10 दिनों के लिए दिनांक 27 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक आयोजित हुआ। मेला का उद्घाटन 27 जनवरी को मुख्य अतिथि सुमित्रा देवी (समाजसेवी) धनबाद सांसद ढुलू महतो की धर्मपत्नी द्वारा मेला संयोजक अनिल गोयल, अजय कुमार उपाध्याय संगठक, प्रांत संयोजक राजेश उपाध्याय, क्षेत्रीय संयोजक अमरेन्द्र कुमार सिंह की उपस्थिति में भारत माता को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मंत्र उच्चारण के बीच संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मंच के क्षेत्रीय संगठक अजय उपाध्याय ने कहा कि 147 करोड़ मानव शक्ति के अंदर स्वदेशी जागरण मंच मेला के माध्यम से स्व के भाव को जगाने का काम कर रही है। ताकि हमारे देश के लोग जब भी बाजार जाए तो खाने से लेकर पहने और हर इस्तेमाल के वास्तु में सर्वप्रथम स्वदेशी को प्राथमिकता दे ताकि हमारे जीवन के संपूर्ण चतुर्दिक दिशाओं में ऐसा स्व का बोध जागे। वही कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ने कहा कि स्वदेशी वस्तु का इस्तेमाल कर हम अपने देश को आर्थिक रूप से सबल बना सकते हैं। इसमें झारखंड इसका जीता जागता उदाहरण है। यहां के हस्त निर्मित वस्तुओं की मांग पूरे विश्व में बढ़ी है।

कार्यक्रम का संचालन अजय चौधरी दीपक ने किया, वहीं स्वागत भाषण सह प्रांत प्रमुख अजय सिंह ने किया। जबकि विषय प्रवेश दिलीप कुमार वर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन जिला संयोजक प्रमोद कुमार सिन्हा ने किया। इस पूरे कार्यक्रम में अनुजा सिंह, पूनम सिन्हा, अनीता सिंह, पूनम सिंह, आशा सिन्हा, दिलीप वर्मा, अजय कुमार सिंह, कुमार संजय, जयशंकर प्रसाद, मनीष श्रीवास्तव, सुजीत कुमार, राकेश रंजन, नवीन सिन्हा संजय श्रीवास्तव, अनंत शेखर समेत अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थें।

स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में बजट पर चर्चा

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डॉ राजीव कुमार ने कहा कि इस वर्ष का बजट चुनावी बजट की बजाय, दूरदर्शिता को ज्यादा दिखा रहा है और भारत को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। बजट में पूंजीगत खर्च को बढ़ाकर

12.2 लाख करोड़ किया गया है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, और हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर पर जोर दिया गया। यह बजट आत्मनिर्भरता, विकास और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट और अनुभवी एजुकेटर सीए अभिनव अग्रवाल ने केंद्रीय बजट की संरचना, प्रमुख प्रावधानों, और कर प्रणाली में हुए परिवर्तनों को सरल और सशक्त प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समझाया। उन्होंने बताया कि बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होता है।

मंच के वरिष्ठ आयाम प्रमुख डॉक्टर एके अग्रवाल ने कहा कि यह बजट विकसित भारत का खाका है। इसमें आकर्षण कम वित्तीय अनुशासन अधिक है। अंत में सी ए हिमांशु मेहरा ने बजट को संतोषजनक बताते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन प्रांत संयोजक कपिल नारंग ने किया। कार्यक्रम में एक इंटरएक्टिव प्रश्न–उत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बजट, टैक्सेशन, सरकारी योजनाओं, और आर्थिक नीतियों से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे। सीए अभिनव अग्रवाल ने सभी प्रश्नों का विस्तारपूर्वक और व्यवहारिक उदाहरणों के साथ उत्तर दिया। सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया।

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्यक्रम आयोजित

स्वदेशी जागरण मंच, जिला ऊना की ओर से युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगा, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत की भावना से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्वदेशी विचारधारा को व्यवहार में उतारते हुए समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। यह जानकारी स्वदेशी जागरण मंच जिला पूर्णकालिक सत्य देव शर्मा सहोड़ ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रथम आयोजन जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), ऊना में किया गया, जहां स्वरोजगार, स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भर बनने के विषय पर एक विस्तृत कार्यशाला आयोजित हुई। इस कार्यशाला में आईटीआई के लगभग 70 प्रशिक्षु विद्यार्थियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री विनय शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे।

मुख्य वक्ता विनय शर्मा ने अपने संबोधन में युवाओं को

तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ उद्यमिता, स्टार्टअप संस्कृति, लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा स्वरोजगार की संभावनाओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनने की सोच विकसित करनी चाहिए। स्वदेशी उत्पादों के निर्माण और उपयोग से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र – तीनों स्तरों पर आत्मनिर्भरता सशक्त होती है। उन्होंने युवाओं से स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने और स्वदेशी को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

इसी क्रम में दूसरा कार्यक्रम महिला मंडल बहडाला में आयोजित महिला संगोष्ठी के रूप में संपन्न हुआ। इस संगोष्ठी में करीब 42 महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यहां भी क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री विनय शर्मा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, आर्थिक स्वावलंबन, घरेलू एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण तथा स्वदेशी उत्पादों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

स्वदेशी जागरण मंच, जिला ऊना ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के जागरूकता, प्रशिक्षण एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को स्वदेशी एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ा जा सके। इस दौरान आईटीआई के प्रिंसिपल अंशुलशु भारद्वाज, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बलबीर बग्गा, महिला मंडल वहडाला की प्रधान प्रवीण राणा, संध्या देवी, पूर्व पंचायत प्रधान उप प्रधान सुरेश कुमार व शिल्पी सोनी सुमित अनेक महिलाएं उपस्थिति रही।

https://encounterindia.in/swadeshi-jagran-manch-organised-a-programme-with-the-aim-of-connecting-with-the-spirit-of-self-reliant-india/

करनाल में स्वदेशी जागरण मंच का विशेष सत्र आयोजित

स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में बृहस्पतिवार को जेनिसिस क्लासिस, करनाल में एक विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस सत्र का उद्देश्य छात्रों को स्वदेशी सुरक्षा, आत्मनिर्भरता एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक

करना रहा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि आज का युवा वर्ग संगठित प्रयासों के माध्यम से भारत को समृद्ध, सुरक्षित एवं स्वावलंबी राष्ट्र बना सकता है। वही आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण के प्रमुख सहयोगी होंगे। मुख्य वक्ता कुलदीप पुनिया, प्रचारक एवं प्रांत संगठन, स्वदेशी जागरण मंच ने छात्रों को देश के महान वीर सपूतों के जीवन से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि सभी को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जेनिसिस क्लासिस के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र सिंह ने नीट एवं जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जो विद्यार्थी अपने माता–पिता एवं गुरुओं के मार्गदर्शन में चलते हैं तथा गीता के श्लोकों का अध्ययन करते हैं, वे जीवन में कभी असफल नहीं होते। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि सभी मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनें और विश्व मंच पर भारत का तिरंगा गौरवपूर्वक लहराएं।

कार्यक्रम में सतीश चावला (पूर्णकालिक पालक, अखिल भारतीय स्वदेशी जागरण मंच), भजन लाल (जिला पूर्णकालिक, करनाल), डॉ. विकास अत्री (सेवानिवृत्त जिला उच्च शिक्षा अधिकारी) एवं प्रेम प्रकाश ढींगरा(कार्यकर्ता, स्वदेशी जागरण मंच) सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

https://www.dainiktribuneonline.com/news/karnal/special-session-of-swadeshi-jagran-manch-organized-at-genesis-classes-karnal/

रामपुर में स्वदेशी की छात्र रैली

रामपुर में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बापू समाधि स्थल से एक छात्र जागरूकता रैली निकाली गई। नगर विधायक आकाश सक्सेना ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और छात्र–छात्राओं को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि छात्र ही देश की असली ताकत हैं और इन्हीं से स्वदेशी क्रांति आएगी। इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। वे हाथों में स्वदेशी के समर्थन में तख्तियां लिए हुए थे और पूरे जोश के साथ नारे लगा रहे थे। यह आयोजन स्वदेशी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था।

रैली के दौरान विधायक आकाश सक्सेना ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और उनकी क्रांतिकारी सोच समाज को नई दिशा दे सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बच्चों के सहयोग से पहले रामपुर, फिर प्रदेश और अंततः पूरे देश में स्वदेशी की क्रांति फैलेगी।

मीडिया से बातचीत में नगर विधायक ने बताया कि स्वदेशी केवल एक विचार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने जोर दिया कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आम जनता से भी विदेशी उत्पादों के बजाय स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की अपील की।

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/rampur/news/rampur-swadeshi-jagran-manch-student-rally-akash-saxena-137061667.html

छात्राओं को दिलाई स्वदेशी अपनाने की शपथ

फरीदाबाद सेक्टर–16ए स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करने तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने रहा। इसमें एडवोकेट राजेंद्र शर्मा तथा ऐश्वर्या वशिष्ठ मुख्य वक्ता रही। छात्राओं को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई तथा एक मैराथन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य घनश्याम दास ने किया। कार्यक्रम के उपरांत छात्राओं एवं स्टाफ के लिए एक उत्साहपूर्ण मैराथन दौड़ का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडवोकेट राजेंद्र शर्मा एवं एडवोकेट ऐश्वर्या वशिष्ठ ने स्वदेशी अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को प्रेरित किया।

उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग से आर्थिक आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन तथा राष्ट्रीय गौरव की प्राप्ति पर बल दिया। मुख्य वक्ताओं ने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी को जीवन का हिस्सा बनाएं, जिससे भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बने। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. घनश्याम दास ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा अपने संबोधन में स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान प्रासंगिकता पर चर्चा की। उन्होंने छात्राओं को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई तथा महाविद्यालय की ओर से इस प्रकार के आयोजनों को निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन बलराम यादव ने कुशलतापूर्वक किया, जिन्होंने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को रोचक बनाए रखा। ❑❑

https://www.livehindustan.com/ncr/faridabad/story-promoting-swadeshi-event-at-faridabad-college-to-foster-self-reliant-india-201769079467308.html

स्वदेशी कार्यक्रम

सचित्र झलक

बजट चर्चा - कानपुर

वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ कार्यक्रम, नई दिल्ली

स्वदेशी मेला - सरायकेला (झारखंड)

स्वदेशी परिवार सम्मेलन - जमशेदपुर (झारखंड)

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 फरवरी 2026
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

सचित्र झलक

अखिल भारतीय स्वदेशी संकल्प यात्रा

बजट पर चर्चा

राउरकेला, उड़ीसा

भुवनेश्वर, उड़ीसा

कोरापुट, उड़ीसा

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती